● वर्ष : 17 ● अंक : 239 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

दिल्ली से प्रकाशित शुक्रवार 19 जून 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

मध्य पूर्व में शांति का नया अध्याय

अमेरिका-ईरान समझौते पर ट्रंप और पेजेशकियन ने किए हस्ताक्षर

एजेंसी। पेरिस (फ्रांस)

मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के मसौदे पर प्रारंभिक सहमति बन गई है। मसौदे में सैन्य गतिविधियों को रोकने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, ईरान के पुनर्निर्माण में सहयोग और परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार शाम फ्रांस के वर्साय पैलेस में आयोजित रात्रिभोज के दौरान अमेरिका-ईरान समझौते के मसौदे पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस और फॉक्स न्यूज ने अपने एक्स हैंडल पर सबसे पहले इसकी पुष्टि की। इसके बाद यह खबर दुनिया में आग की तरह फैल गई। ईरान के प्रेस टीवी, गल्फ न्यूज, अल जजीरा, सीएनएन, टाइम पत्रिका और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने, प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत और 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते की दिशा में कदम शामिल हैं। बताया जाता है कि ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अमेरिका ने इस दस्तावेज को 'संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' के रूप में जारी किया है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत खोलना, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार से जुड़े मुद्दों का समाधान करना और प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने पुष्टि की कि समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देकर दोनों पक्षों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर ओमान और अन्य देशों के साथ काफी समय से परामर्श चल रहा था। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन से जुड़े अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी। बघाई ने कहा कि अब समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। होर्मुज जलडमरूमध्य पर इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता और अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

मसौदे के 14 बिंदु

1- सभी तरह के संघर्ष रुकेंगेः अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देशों ने तत्काल प्रभाव से सभी सैन्य अभियानों को समाप्त करने और भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करने का संकल्प लिया है। इसमें लेबनान से जुड़े संघर्ष भी शामिल हैं। लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा।

2- एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मानः दोनों देश एक-दूसरे की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएंगे.

3- 60 दिनो में अंतिम समझौते का लक्ष्य।

4- अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटेगीः इसमें शर्त है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकाबंदी और अन्य बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 30 दिन के भीतर इसे पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

5- होर्मुज जलडमरूमध्यः ईरान 60 दिन तक फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच वाणिज्यिक जहाजों को मुफ्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराएगा। तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने तथा समुद्री बारूदी सुरंगों की सफाई के बाद 30 दिन में यातायात सामान्य स्तर पर पहुंचाने की योजना है।

6- ईरान के लिए 300 अरब डॉलर की आर्थिक योजना।

7- प्रतिबंध हटाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

8- ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। दोनों देश संवर्धित परमाणु सामग्री के निपटारे, यूरेनियम संवर्धन और अन्य परमाणु जरूरतों पर अंतिम समझौते के तहत विस्तृत चर्चा करेंगे।

9- वार्ता के दौरान यथास्थिति बनी रहेगी।

10- तेल निर्यात को तत्काल राहतः एमओयू लागू होते ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा तथा परिवहन सेवाओं के लिए विशेष छूट जारी करेगा।

11- अमेरिका ईरान की फ्रीज या प्रतिबंधित संपत्तियों और धनराशि को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत।

12- निगरानी तंत्रः समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

13- अंतिम समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू होगी।

14- अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के जरिए वैधता प्रदान की जाएगी।

फ्रांस में प्रमुख उद्योगपतियों से मिले मोदी, निवेश और भारत में विस्तार योजनाओं पर चर्चा

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/ प्रकाशक। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान गुरुवार को कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और भारत में निवेश के अवसरों तथा कारोबार विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निर्माण सामग्री क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सेंट-गोबेन के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बेनोइट बाजिन से मुलाकात की। बातचीत में निर्माण सामग्री और अवसंरचना क्षेत्र में अवसरों, विशेषकर टिकाऊ विकास से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। मोदी ने भारत में सेंट-गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारतीय युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का सृजन हो रहा है। बाजिन ने भारत में कंपनी के निवेश और विस्तार की भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने रेल परिवहन और गतिशीलता क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एल्सटॉम के सीईओ मार्टिन सियोन से भी मुलाकात की। इस दौरान रेलवे आधुनिकीकरण और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मोदी ने भारत में एल्सटॉम के निवेश और विनिर्माण गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ भारतीय रेल क्षेत्र के विकास को भी गति मिली है। सियोन ने भारत में कंपनी के विस्तार और अतिरिक्त निवेश की योजनाओं से अवगत कराया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मिस्ट्राल एआई के सह-संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंश से भी मुलाकात की। मोदी ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे एआई पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध अवसरों को रेखांकित किया। आर्थर मेंश ने भारत के साथ सहयोग और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर नवाचार को बढ़ावा देने तथा एआई क्षमताओं के विस्तार में गहरी रुचि व्यक्त की।

संक्षिप्त समाचार

बैंक धोखाधड़ी मामलों में कोलकाता की 8 जगहों पर सीबीआई की एकसाथ छापेमारी

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े तीन अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी मामलों में बुधवार (17 जून) को कोलकाता के 8 विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मैसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मैसर्स ब्रह्म अलॉयज लिमिटेड और मैसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में की गई है। इन तीनों मामलों के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को कुल 191 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है। सीबीआई के अनुसार, पहले मामले में एजेंसी ने मैसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशकों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली। यह मामला बैंक से प्राप्त कैश क्रेडिट और टर्म लोन सुविधाओं में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 73 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोपितों ने बैंक से प्राप्त फंड को अपनी सहायक और सहयोगी कंपनियों की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण और गैर-मानक खातों के माध्यम से एक बड़ी राशि ट्रांसफर कर डायवर्ट किया था। दूसरे मामले में मैसर्स ब्रह्म अलॉयज लिमिटेड के निदेशकों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई। यह मामला बैंक से ली गई कैश क्रेडिट सुविधा में पीएनबी को 58 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने से संबंधित है।

मोदी सरकार के 12 साल विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम युग : शाह

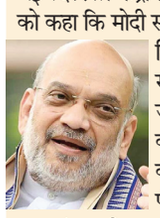

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार के 12 साल विकास और

विरासत के संगम का स्वर्णिम युग रहे हैं। इन 12 सालों में, एक ओर जहां राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर पीएम आवास, आयुष्मान भारत, अन्न भंडार, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार विकास भी, विरासत भी की थीम के तहत पिछले 12 सालों में की गई पहलों को उजागर कर रही है। सरकारी बयान के मुताबिक विरासत संरक्षण को व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, विकास और प्रचार-प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बयान में कहा गया है कि मुख्य पहलों में एक करोड़ रिकॉर्ड का डिजिटाइज़ेशन, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के 11 म्यूज़ियम बनाना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में मशहूर जगहों को फिर से ठीक करने, आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और हेरिटेज शहरों व तीर्थयात्रा सर्किट को विकसित करने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक संपत्तियां जिनमें स्मारक, प्राचीन वस्तुएं, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं पीढ़ियों से चली आ रही एक साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं।

पीएम-किसान की 23वीं किस्त 20 जून को होगी जारी 9.44 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 18,880 करोड़

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थियों में 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित कई केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

कृषि मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी की गई जानकारी के अनुसार : पश्चिम बंगाल के 45.35 लाख से अधिक किसानों को 907.21 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके साथ ही वर्ष 2019 से अब तक राज्य में पीएम-किसान के तहत कुल वितरण 15,055 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल हैं। फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2026-27 में पश्चिम बंगाल के लगभग 1.10 करोड़ किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

पीएम मोदी और ट्रंप ने की व्यापार समझौते रक्षा संबंधों और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा

एजेंसी। पेरिस

दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत संबंधों और आपसी तालमेल को मजबूत करने दोहराई प्रतिबद्धता

पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत में बढ़ोतरी, रक्षा संबंधों को सुनिश्चित करने और पश्चिम एशिया से लेकर ग्लोबल शिपिंग रूट्स तक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और आपसी तालमेल को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर जब राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा कि अमेरिका और भारत व्यापार डील से कितने दूर हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत करीब। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे मुश्किल नेगोशिएटर में से एक बताया। ट्रंप ने कहा कि हमले की हालत में अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। रक्षा संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उन पर हमला होता है, तो हम उनकी मदद के लिए वहां होंगे। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थिरता वापस लाने के लिए ट्रंप की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि ट्रंप की कोशिशों की वजह से इस इलाके में शांति और स्थिरता की नई उम्मीद फिर से जगी है। दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आप और मैं इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल, भारत होर्मुज स्ट्रेट पर ऊर्जा सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा निर्भर है।

शिवसेना (यूबीटी) की बैठक में शामिल नहीं हुए पार्टी के 6 सांसद

नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले छह लोकसभा सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी व्हिप की अवहेलना को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। पार्टी की ओर से दिए गए व्हिप के बावजूद छह सांसद अनुपस्थिति रहे। इनमें संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश पाटिल अष्टिकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी) और ओमप्रकाश उर्फ ओम राजे निम्बालकर (धाराशिव/उस्मानाबाद) शामिल हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दावा है कि शिवसेना (यूबीटी) के अधिकांश सांसद दल बदलने को तैयार हैं। बैठक में तीन सांसद उपस्थित थे। इनमें अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण-मध्य) और राजभाऊ वाजे (नासिक) शामिल हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने बताया कि संसदीय दल की बैठक लोकसभा के फ्लोर लीडर अरविंद सावंत और मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बुलाई थी।

सरकारी नौकरी का झांसा देकर 12.5 लाख की ठगी! राष्ट्रपति भवन में नौकरी दिलाने का दावा करने वाले प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप

लोकतंत्र की शान। नई दिल्ली

- पीड़ित ने लगाया धोखाधड़ी, धमकी और अवैध वसूली का आरोप; वीडियो कॉल पर बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी दावा

सरकारी नौकरी पाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। संगम विहार निवासी इस्ताक मोहम्मद ने प्रताप सिंह नामक व्यक्ति पर राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित इस्ताक मोहम्मद के अनुसार, उनकी मुलाकात 1 जुलाई 2024 को आंध्र भवन कैंटीन में प्रताप सिंह से हुई थी। प्रताप सिंह ने स्वयं को राष्ट्रपति भवन में कार्यरत बताते हुए अपना परिचय पत्र दिखाया और कई प्रभावशाली लोगों से परिचय कराने का दावा किया। इसके बाद उसने राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय में ग्रुप-सी की सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसमें 42 हजार रुपये वेतन और सरकारी आवास मिलने की बात कही गई। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने सरकारी लेटरहेड, फॉर्म और अन्य दस्तावेज दिखाकर उनका विश्वास जीता और धीरे-धीरे नौकरी लगवाने के नाम पर विभिन्न बहानों से लाखों रुपये वसूल लिए। कभी सरकारी खाते खुलवाने, कभी पासपोर्ट, ओबीसी प्रमाण पत्र, तो कभी मंत्रालयों के अधिकारियों से फाइल पास कराने के नाम पर लगातार पैसों की मांग की जाती रही। इस्ताक मोहम्मद का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी, पीएफ की रकम और उधार लेकर आरोपी को लगभग 7.5 लाख रुपये नकद तथा करीब 5 लाख रुपये ऑनलाइन माध्यम से दिए। यह लेनदेन अलग-अलग समय पर दिल्ली के विभिन्न स्थानों जैसे जंतर-मंतर, आंध्र भवन

कैंटीन, नॉर्थ एवेन्यू और अन्य सरकारी परिसरों के आसपास हुआ। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बंदूक दिखाकर कहा कि "जहां शिकायत करनी है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि आरोपी बार-बार अपना मोबाइल नंबर बदलता रहा और अब पैसे लौटाने से साफ इनकार कर रहा है। साथ ही उसने झूठे मुकदमे में फंसाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी है। इस्ताक मोहम्मद ने प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि यदि उनके या उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की होगी। उन्होंने अपने पास मौजूद बैंक लेनदेन के रिकॉर्ड, व्हाट्सएप कॉल डिटेल, फोटो और अन्य दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंपने की बात कही है। फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।नोटः यह समाचार पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों और उसके लिखित बयान पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित जांच एजेंसी द्वारा की जानी शेष है।

टोल नहीं होर्मुज से गुज़रते वक्त दी जाने वाली सेवाओं के बदले शुल्क लेगा ईरान?

एजेंसी। नई दिल्ली

होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर भारी मात्रा में कच्चे तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। इस जलमार्ग में होने वाला कोई भी व्यवधान दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है। अब महीनों से चले आ रहे अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद जब यह जलमार्ग फिर से खुलने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि होर्मुज स्थायी रूप से टोल-फ्री रहेगा। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है -पनामा और स्वेज नहर से गुज़रने के लिए जहाज़ों को चुकानी पड़ती है बड़ी रकम कि वाणिज्यिक जहाजों को अभी भी पारगमन के दौरान दी जाने वाली

सेवाओं से जुड़े भुगतान करने की जरुरत हो सकती है। इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। दुनिया भर में होने वाले पेट्रोलियम शिपमेंट का लगभग पांचवां हिस्सा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के निर्यात का करीब एक-चौथाई हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए एक समझौते में युद्ध खत्म करने और जलमार्ग को फिर से खोलने की शर्तें तय की गई हैं। इसका असर फ़ाइनेंशियल मार्केट पर दिखा। तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि ट्रेडर्स को उम्मीद थी कि खाड़ी देशों से एनर्जी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने घोषणा की कि होर्मुज़ फिर से खुल जाएगा और वहां से गुज़रने के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। उनके बयानों का मकसद मार्केट को भरोसा दिलाना और महीनों की अस्थिरता के बाद समुद्री कामकाज के सामान्य होने का संकेत देना था। हालांकि, अगले ही दिन ईरान ने अपना रुख साफ किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान का सीधे ट्रांज़िट टोल लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि जलडमरूमध्य से गुज़रने के दौरान दी जाने वाली सेवाओं के लिए जहाजों को शुल्क देना पड़ सकता है।

संक्षिप्त समाचार

उपराष्ट्रपति ने नशामुक्त परिसर अभियान के तहत दिल्ली विवि के प्रयासों की सराहना की

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने नशामुक्त अभियान परिसर के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की।उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान और ई-प्रतिज्ञा मंच के शुभारंभ को याद करते हुए छात्रों से नशामुक्त भारत के राजदूत बनने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ खड़े होने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से 53,000 से अधिक छात्रों ने अनिवार्य शपथ ली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल एक स्वस्थ, मजबूत और अधिक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।उपराष्ट्रपति ने देशभर के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से इस प्रयास में शामिल होने और अपने छात्रों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नशामुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास और युवाओं में निरंतर जागरूकता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज सभी को संकल्प लेना चाहिए कि नशामुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों से खुद भी दूर रहेंगे और सभी को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने सभी को मादक पदार्थों से सतर्क रहने, दोस्तों को इससे उबारने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाकर उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 13 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय में नशामुक्त परिसर अभियान आरम्भ किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्ति को समर्पित ई-संकल्प मंच और मोबाइल एप्लिकेशन का भी शुभारंभ किया और देश के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से भाग लेने और नशा मुक्त परिसर का संकल्प लेने की अपील की।

आईसीएआई सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित, पटियाला के नूर सिंगला बने ऑल इंडिया टॉपर

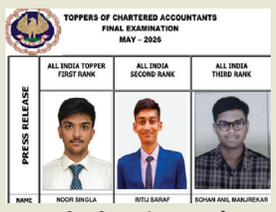

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने गुरुवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फाइनल मई, 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आईसीएआई ने टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी है। इस बार पटियाला के नूर सिंगला ने 499 अंक (83.17 फीसदी) हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। आईसीएआई ने सीए फाइनल मई 2026 परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया। साथ ही टॉपर्स की सूची भी जारी कर दी गई है। इस बार पटियाला के नूर सिंगला ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया, उन्हें 499 अंक मिले हैं, जबकि उनका फीसदी 83.17 रहा। हावड़ा के रितिज सराफ ने 475 अंकों यानी 79.17 फीसदी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि डोंबिवली के सोहन अनिल मांजरेकर 473 अंकों यानी 78.83 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इन तीनों छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया टॉप-3 में अपनी जगह बनाई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीए फाइनल परीक्षा पास करने के बाद 7,931 उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट बने है। ग्रुप I के 54,606 उम्मीदवारों में से 6,555 पास हुए। ग्रुप II का परिणाम 20.49 फीसदी रहा और 42,573 उम्मीदवारों में से 8,725 पास हुए। दोनों ग्रुप का परिणाम 14.07 फीसदी रहा है, जिसमें 23,776 उम्मीदवारों में से 3,345 पास हुए हैं।

दिल्ली के सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण लागू करने का निर्देश

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश गुरुवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति को लेकर समीक्षा बैठक में दिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह आरक्षण भारत सरकार के विजन के अनुरूप लागू किया जा रहा है।तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते कहा कि इन युवा पुरुषों और महिलाओं के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड सहित ग्रुप 'सी' के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20 फीसद आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया गया।

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है आज दिनांक 17/6/2026 से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र मौ सलमान पिता शमीम अहमद , निवासी ग्राम भगुवाला, पोस्ट भगुवाला, थाना मड़ावली, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया है तथा उसके व्यवहार के कारण परिवार उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। यदि कोई व्यक्ति उसके साथ किसी प्रकार का लेन-देन, उधार, खरीद-फरोख्त अथवा अन्य कोई कार्य करता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति की होगी। परिवार की ओर से किसी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं

मुख्यमंत्री ने जन कल्याण शिविर का किया शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिल्लीवासियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आज संदेश विहार स्थित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कम्युनिटी हॉल में जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण की प्रेरणा से दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक राजधानी के 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर आयोजित कर रही है, जहां केंद्र एवं दिल्ली सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण एवं सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाने का आग्रह किया है। इसके अलावा दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) सामुदायिक केंद्र, बंगाली मार्केट में जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से केंद्र एवं दिल्ली सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए शिवरों को आयोजन किया जा रहा है।

वन नेशन, वन एक्सपो' थीम के तहत भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। देश में निर्माण सामग्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूती देने के लिए 'वन नेशन, वन एक्सपो' प्रदर्शनी का गुरुवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया गया। पहले दिन यहां 25 हजार से अधिक आगंतुक प्रदर्शनी देखने आए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग के लिए आयोजित प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026, 'वन नेशन, वन एक्सपो' का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने निर्माण एवं भवन सामग्री उद्योग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया।इस अवसर पर अपने संबोधन में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उद्योगों के लिए अवसरों के विस्तार में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच बढ़ने के साथ ही साथ व्यापार संबंधों के मजबूत होने की आशा है, जिससे भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे।जितिन प्रसाद ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का भी उल्लेख किया, जिसमें गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए भारत को भरोसेमंद वैश्विक विनिर्माण और सोर्सिंग गंतव्य के तौर पर स्थापित करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भारत के पास निर्माण एवं भवन सामग्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमताएँ और संसाधन मौजूद हैं। प्रसाद ने कहा कि भारत बिल्डकॉन जैसे मंच निर्माताओं, नवप्रवर्तकों, खरीदारों, नीति-निर्माताओं और उद्योग हितधारकों के बीच संवाद को सुगम बनाते हैं, इसके साथ ही इस क्षेत्र में अधिक सहयोग और व्यावसायिक अवसरों के विस्तार में योगदान देते हैं। यह प्रदर्शनी आगामी दिनों में भी जारी रहेगी और उद्योग सहभागिता, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा व्यावसायिक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करेगी।मंत्रालय के मुताबिक भारत बिल्डकॉन 2026 में 90 से ज्यादा देशों और भारत के 100 से अधिक शहरों की भागीदारी है। इस प्रदर्शनी में सिरेमिक्स और स्टोन, हार्डवेयर, सीमेंट और स्टील, प्लाइवुड और लैमिनेट्स, फर्नीचर, सैनिटरीवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, पेंट्स, निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित 24 खंडों में उत्पादों, तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है।उल्लेखनीय है कि यह प्रदर्शनी भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, ठेकेदारों, निर्माताओं, व्यापारियों, नीति-निर्माताओं, उद्योग संघों तथा अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को एक साथ लाती है, जिससे उद्योग के बीच संवाद और व्यावसायिक सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध होता है।

दिल्ली सरकार नीट परीक्षा के 97 केंद्रों के बाहर बनाएंगी कूलिंग जोन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। देशभर में 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर कूलिंग जोन बनाएगी।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में बताया कि दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 69 सरकारी विद्यालय में तथा 28 केंद्रीय विद्यालयों में हैं। इन परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन द्वारा विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों और परिजनों के बैठने, विश्राम करने तथा गर्मी से राहत पाने की समुचित व्यवस्था रहेगी।उन्होंने कहा कि हर वर्ष लाखों परिवार अपने बच्चों के भविष्य के सपनों के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी तो केंद्र के भीतर होते हैं, लेकिन बाहर कई घंटे तक प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता की चिंता, धूप, गर्मी और असुविधा पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली सरकार ने इस मानवीय पहलू को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि परीक्षा के दिन अभिभावकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।उन्होंने कहा कि अब तक अक्सर देखा जाता था कि परीक्षा के दौरान परिजन कभी किसी पेड़ की छांव तलाशते थे, कभी पार्क में बैठकर समय बिताते थे, तो कभी आसपास की बाजारों में इधर-उधर भटकते रहते थे। कई लोगों को भीषण गर्मी में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर ही उनके लिए आरामदायक प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिविजनल कमिश्नर के निर्देश से संबंधित अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास कूलिंग जोन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इन कूलिंग जोन में बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ओआरएस, चाय तथा प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दिल्ली सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और भविष्य में देशभर में परीक्षाओं के दौरान अभिभावकों की सुविधा को भी समान महत्व दिया जाएगा। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही है।मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार केवल परीक्षा केंद्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भीषण गर्मी से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पहले से व्यापक इंतजाम कर रही है। इसके तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों में 85 शेड स्थापित किए गए हैं, 15 कूलिंग जोन संचालित हो रहे हैं तथा 13 मोबाइल राहत वैन लगातार विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को गर्मी से राहत पहुंचा रही हैं। नीट परीक्षा के दौरान अभिभावकों के लिए की गई विशेष व्यवस्था भी इसी जनकल्याणकारी और संवेदनशील सोच का विस्तार है।

होटल, खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रतिष्ठानों को जंग लगे चाकू-ब्लेड का इस्तेमाल न करने के निर्देश

लोकतंत्र की शान

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देशभर में होटल और खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रसंस्करण, कटाई और पैकेजिंग में केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड तथा अन्य कटिंग उपकरणों का ही उपयोग करें।एफएसएसएआई ने गुरुवार को सलाह जारी करते हुए कहा कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में जंग लगे, टूटे-फूटे, चिप्ड या खराब कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भोजन में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। एफएसएसएआई के प्रमुख निर्देशों में केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड व कटिंग उपकरणों का उपयोग करने के साथ उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव करने, सफाई, सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम हाल ही में खाद्य पैकेजिंग में स्टेपल पिन के उपयोग पर रोक लगाने के बाद खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नया डार्क वेब करार दिया, जिसके जरिये अवैध गतिविधियां और गैरकानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बन चुका है। इसके जरिये अपराधी अपने गैरकानूनी कार्य कर पाने में सक्षम हैं। इसके जरिये अपराध करने वालों को पकड़ पाना जांच एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल है। हलफनामा में कहा गया है कि नीट परीक्षा में टेलीग्राम का जमकर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से नीट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा।उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी कानून की धारा 69ए के तहत केवल 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक का आदेश दिया है। दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम 30 जून तक एडिट करने के फीचर को बंद कर दे। केंद्र सरकार ने कहा कि 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए ये आदेश जरुरी है।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी भी पेश हुए। अटार्नी जनरल ने कहा कि केंद्र का आदेश अपने आप में पूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे देश में अगर निरोधात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। अटार्नी जनरल ने कहा कि मुनाफे के लिए बनाया गया प्लेटफार्म आनुपातिकता के सिद्धांत का हवाला नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी दूसरे प्लेटफार्म को नहीं छुआ है। वे ज्यादा ताकतवर हैं लेकिन उनका अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टेलीग्राम से पूछा कि मान लीजिए कि पेपर लीक हुआ है। आदेश भले ही आपको आए लेकिन नुकसान तो हो चुका है। ऐसे में आपका क्या प्रस्ताव होना चाहिए। इससे कैसे निपटा जाए। तब टेलीग्राम ने कहा कि हमने सभी मानदंडों को पूरा किया है। टेलीग्राम की ओर से पेश वकील ध्रुव मेहता ने अनुराधा भसीन के उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र किया।कोर्ट ने 17 जून को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। टेलीग्राम ने कहा है कि आईटी रुल्स के रुल 9 के तहत इसका इस्तेमाल आपात स्थितियों में किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 69ए का इस्तेमाल किया है जो कानूनसम्मत नहीं है। केंद्र सरकार के आदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की शिकायत की गई है। टेलीग्राम का कहना कि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी देखते हैं और अपनी अनुशंसा देते हैं। संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने चैनल को ब्लॉक करने की कोई अनुशंसा नहीं की है। संबंधित अधिकारी और मंत्रालय के बीच हुई बात और टेलीग्राम की कार्रवाई का केंद्र सरकार के आदेश में कोई जिक्र नहीं है। टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके 15 करोड़ यूजर्स हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से उसके यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है।नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम ऐप के इस्तेमाल की बात सामने आयी थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस ऐप को 22 जून तक अस्थायी रुप से बंद करने का आदेश जारी किया। मंत्रालय के एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप किसी मैसेज को एडिट करने के फीचर को 30 जून तक डिसेबल करे। टेलीग्राम ने मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

दिल्ली विधानसभा ने 2026-27 के लिए सदन की 32 समितियों का किया गठन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली विधानसभा ने विधायी वर्ष 2026-27 के लिए सदन की 32 समितियों का गठन कर दिया है। उन्होंने सभी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि ये समितियां विधानसभा की कार्यकुशलता, जवाबदेही एवं जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी अनुश्रवण को और अधिक सुदृढ़ करेंगी।कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे। सरकारी आश्वासन समिति के सभापति दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट होंगे। याचिका समिति के सभापति मनोज कुमार शौकीन होंगे। नियम समिति के सभापति अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता करेंगे। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट होंगे। सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता होंगे। इसके साथ ही पुस्तकालय समिति के सभापति भी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता होंगे। प्रतिनिहित विधायन समिति के सभापति प्रवेश रत्न होंगे। वहीं विशेषाधिकार समिति के सभापति प्रद्युम्न सिंह राजपूत होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति कैलाश गंगवाल होंगे। इसके साथ ही सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सभापति गोपाल राय होंगे। महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति पूनम शर्मा करेंगी। वहीं छात्र एवं युवा कल्याण समिति के सभापति आहिर दीपक चौधरी होंगे। पर्यावरण समिति के सभापति अनिल कुमार शर्मा होंगे। इसके साथ ही आचरण समिति के सभापति करतार सिंह तंवर होंगे।अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति तरविन्दर सिंह मारवाह होंगे, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समित के सभापति राज करण खत्री होंगे। अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मामलों की समिति के सभापति कुलदीप सोलंकी होंगे। इसके साथ ही सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित सदन की समिति के सभापति मुख्य सचेतक अभय कुमार वर्मा होंगे। सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानकों के उल्लंघन एवं विधायकों के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार के संबंध में समिति के सभापति कैलाश गहलोत होंगे। वहीं दिल्ली नगर निगम समिति के सभापति ओम प्रकाश शर्मा होंगे।शांति एवं सद्भाव संबंधी समिति के सभापति उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट होंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के सभापति तिलक राम गुप्ता होंगे। ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजन कल्याण समिति के सभापति करनैल सिंह होंगे, वहीं प्रशासनिक मामलों पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति (जिसके कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक सुधार, सेवाएं, सतर्कता, विधि, न्याय एवं संबंधित निकाय शामिल हैं) के सभापति चंदन कुमार चौधरी होंगे। शिक्षा पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति के सभापति उमंग बजाज होंगे। कल्याण पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति की सभापति नीलम पहलवान होंगी। वहीं स्वास्थ्य पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति के सभापति संजय गोयल होंगे। विकास पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति के सभापति श्याम शर्मा होंगे। इसके साथ जनउपयोगी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति के सभापति संदीप सहरावत होंगे। वित्त एवं परिवहन पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति के सभापति रविंदर सिंह नेगी होंगे।

दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश के आसार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में 19-22 जून के दौरान तेज हवाओं तथा गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। दूसरी ओर देश के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में 19 जून को सुबह या दोपहर के समय 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40-42 डिग्री सेल्सियस और 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।बीस जून को भी यही स्थिति रहेगी। यहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36-38 डिग्री सेल्सियस और 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, 21 जून को दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36-38 डिग्री सेल्सियस और 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं।मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। बीस जून तक विदर्भ, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने की बहुत संभावना है। अगले 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।उत्तर-पश्चिम भारत के 18 से 22 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19-22 जून तक कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में 19-22 जून के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक जा सकती हैं।मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर अगले छह दिनों के दौरान भारी वर्षा होने के आसार हैं। इस बीच, इन क्षेत्रों में तेज रफ्तार की हवाएं चलने की संभावना है।मध्य भारत में 20 जून तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में 20 जून तक धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। पूर्वी और उत्तर प्रदेश में 19-24 जून, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में 19-20 जून के दौरान लू चलने की बहुत संभावना है।उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया था।

संक्षिप्त समाचार

हसनपुर में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन , हजारों कार्यकर्ताओं की हुंकार से गूंजा कमाल पैलेस

लोकतंत्र की शान / सतीश चंद राणा : हसनपुर नगर के कमाल पैलेस में गुरुवार को समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र 42 का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सम्मेलन में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना सदा । कार्यक्रम के बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। सम्मेलन के आयोजक गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख एवं वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि प्रदेश की जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाल स्थिति से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य लगातार पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है, जबकि किसानों को खाद और गैस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए जनहित के मुद्दों पर आवाज बुलंद की। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

भाजपा जन कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भीष्म सिंह खड़गवंशी का हुआ स्वागत

लोकतंत्र की शान , सतीश चंद राणा : हसनपुर में भाजपा जन कल्याण मंच उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भीष्म सिंह खड़गवंशी के कार्यालय पर शुभकामनाएं देने पहुंचे कार्यकर्ता । इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। पूर्व प्रधान धर्मेंद्र सिंह (गढ़वाली), कंचन सिंह (गढ़वाली) एवं डॉ. राकेश सिंह (नवाबपुरा) ने कार्यालय पहुंचकर भीष्म सिंह खड़गवंशी को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनहित के कार्यों को नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर भीष्म सिंह खड़गवंशी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का स्नेह, विश्वास एवं सहयोग उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और समाज सेवा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जन कल्याण मंच जनता की समस्याओं के समाधान एवं जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और संगठन के विस्तार में सहयोग का भरोसा दिलाया।

मुहर्रम को लेकर थाना हजरतनगर गढ़ी में शांति समिति की बैठक आयोजित, पुलिस ने दिए सौहार्द और कानून पालन के निर्देश

लोकतंत्र की शान , सैय्यद कुमैल ज़ैदी ,संभल/ सिरसी थाना हजरत नगर गढ़ी में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं पारंपरिक तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना हजरतनगर गढ़ी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से आए गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी संजय सिंह ने की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। वर्षों से चली आ रही परंपरागत रस्मों और कार्यक्रमों का आयोजन पूर्व की भांति ही किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नई परंपरा शुरू करने, अफवाह फैलाने या शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसआई (वरिष्ठ उपनिरीक्षक) एवं फतेहउल्लागंज चौकी प्रभारी ने उपस्थित लोगों से मुहर्रम को आपसी भाईचारे, अनुशासन और सौहार्द के साथ मनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। इस अवसर पर उपनिरीक्षक एवं सिरसी चौकी प्रभारी फिरोज खान ने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा ताजिया और मुहर्रम जुलूसों के संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, सभी आयोजक उनका पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के कार्यक्रम निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप आयोजित किए जाएं, ताकि क्षेत्र में अमन, शांति और भाईचारे का माहौल कायम रहे।

साहनपुर में विकास कार्यों पर सख्ती गुणवत्ता जांच के बाद ही मिलेगी हरी झंडी

» जनहित सर्वोपरि, तकनीकी मानकों पर खरी सामग्री मिलने पर ही दी जाएगी अनुमति

लोकतंत्र की शान , खिज़र अहमद , नजीबाबाद! साहनपुरनगर पंचायत साहनपुर के अध्यक्ष खुर्शीद मंसूरी ने स्पष्ट किया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में होने वाले किसी भी विकास कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रियाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के धन से होने वाले कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना नगर पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नजीबाबाद विधायक की ओर से क्षेत्र में कुछ लाइटें लगाने के लिए नगर पंचायत से एनओसी (NOC) मांगी गई थी। संबंधित सामग्री की गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों को लेकर संदेह उत्पन्न होने तथा प्रकाश क्षमता अपेक्षाकृत कम पाए जाने के कारण नगर पंचायत ने पहले आवश्यक जांच और परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि यदि जांच के दौरान सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई जाती है तो जनहित से जुड़े किसी भी विकास कार्य में नगर पंचायत की ओर से कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। लेकिन गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी कर किसी भी कार्य को अनुमति देना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनओसी देना या न देना पूरी तरह नियमों, तकनीकी मानकों और जनहित के आधार पर तय किया जाएगा, न कि किसी राजनीतिक दबाव या व्यक्ति विशेष के प्रभाव में। नगर पंचायत का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रवासियों को बेहतर और टिकाऊ सुविधाएं उपलब्ध हों।

निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी ठप रहा नजीबाबाद उप निबंधक कार्यालय

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस खोलने तथा रजिस्ट्री व्यवस्था के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में उप निबंधक कार्यालय नजीबाबाद में दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता एवं स्टांप विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखते हुए सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बृहस्पतिवार को उप निबंधक कार्यालय में सभी दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता तथा स्टांप विक्रेताओं ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया। इसके चलते पूरे दिन एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी, जिससे सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में धरना देकर निजीकरण संबंधी निर्णय को वापस लेने की मांग की। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने कहा कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। संघ के सचिव सौरभ कश्यप ने कहा कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने में मोहम्मद असलम, सौरभ कुमार, शशिकांत, अब्दुल रब, अनवर शरीक, मुकुल शर्मा, शहजाद आलम, एडवोकेट जीशान अख्तर, गोविंद सिंह, रूचिन तोमर, एडवोकेट मेघनाथ, अमित सिंघल, एडवोकेट ओजेश राजपूत, रणधीर सिंह, भानु प्रकाश, गौरव कुमार, एडवोकेट बहार आलम, पंकज अग्रवाल, एडवोकेट फुरकान अहमद, तेजपाल सिंह, मोहम्मद कासिफ, सुनील भटनागर, सरताज अहमद, शादाब, राजीव शर्मा, फहीम उल हसन, सोम कुमार, हरिओम सिंघल, तरुणवीर, हेमराज, राहुल कश्यप, मोहम्मद अहसान, मोहम्मद असगर, मोहम्मद आसिफ, रविराज कश्यप सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टांप विक्रेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निजीकरण संबंधी फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

करबला और जुलूस मार्गों की सफाई युद्ध स्तर पर, चेयरमैन कौसर अब्बास खुद कर रहे निगरानी

लोकतंत्र की शान

संभल/ सिरसी आगामी मोहर्रम को लेकर नगर पंचायत सिरसी में तैयारियां तेज हो गई हैं। चेयरमैन जनाब कौसर अब्बास के नेतृत्व में करबला मोहल्ला सादात शर्की और विभिन्न जुलूस मार्गों पर विशेष सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सफाई, नाला सफाई, प्रकाश व्यवस्था (लाइट्स) और अन्य आवश्यक इंतिज़ामात तेजी से पूर्ण कराए जा रहे हैं, ताकि अज़ादारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खास बात यह है कि चेयरमैन कौसर अब्बास स्वयं दिन-रात मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। वे करबला परिसर और जुलूस मार्गों की साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं, जिससे मोहर्रम के दौरान सभी कार्यक्रम व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिरसी में शायद पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को मोहर्रम की तैयारियों को लेकर इस तरह व्यक्तिगत रुचि लेते हुए दिन-रात मैदान में मौजूद देखा जा रहा है। चेयरमैन कौसर अब्बास की यह सक्रियता केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अज़ादारों और अहलेबैत (अ.स.) की खिदमत का जज़्बा भी साफ दिखाई देता है। नगरवासियों और अज़ादारों ने चेयरमैन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, लगन और समर्पण सिरसी के लिए एक नई मिसाल बन रहे हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि मोहर्रम के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए उनका यह प्रयास आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा।

रामपुर से मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट

» रामपुर नईनवेली 2 दिन की दुल्हन ठगी के मामले में गिरफ्तार

» शादी करने वाले दूल्हे के साथ ही ठगी की वारदात को दिया अंजाम

लोकतंत्र की शान

रामपुर : मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पुनीत नाम का युवक सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करता है और शादी करना चाहता था। आरोप है कि उसके रिश्तेदार कालू और राम सिंह ने उससे कहा कि वे उसकी शादी करा देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने युवक से एक लाख रुपये लेकर यासमीन नाम की महिला से उसकी शादी करा दी। शादी के बाद महिला दो दिन तक ससुराल में रही, लेकिन तीसरे दिन वह घर का सामान समेटकर जाने लगी। युवक को शक होने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया जांच में सामने आया कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे भी हैं। आरोप है कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर युवक से शादी की थी। पुलिस का कहना है कि महिला शादी के नाम पर ठगी कर लोगों का सामान और जेवर लेकर फरार हो जाती थी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर महिला यासमीन समेत कालू और राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपित महिला और उसके साथी पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं या नही

जनता की चौखट तक विकास पहुंचाने में जुटे चौधरी मुशीर अली खान, कई वार्डों में किया स्थलीय निरीक्षण

» संभल में विकास की नई इबारत लिख रहे चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान, तीन वार्डों में सड़कों का निरीक्षण कर जनहित कार्यों को दी रफ्तार

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल। नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के वरिष्ठ नेता एवं चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान ने नगर के विभिन्न वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सड़क निर्माण, जल निकासी और अन्य जनसुविधाओं की जानकारी ली तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। सबसे पहले चौधरी मुशीर अली खान ने वार्ड संख्या-21 में हाजी नूर के होटल से मंडी समिति के कोने तक प्रस्तावित सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं और कहा कि खराब सड़क के कारण लोगों को लंबे समय से आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे जल्द दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने वार्ड संख्या-30 स्थित बशीर गार्डन के पीछे वाली सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की मांग रखी, जिस पर चौधरी मुशीर अली खान ने भरोसा दिलाया कि नगर पालिका द्वारा विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। वहीं, उन्होंने रुकंडी सराय चौराहे से वारिश हॉस्पिटल की पुलिया तक सड़क मार्ग का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से सड़क की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था तथा निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराना उनकी प्राथमिकता है और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की जिम्मेदारी है।

हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टो होंगे हसनपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुनकाद अली ने की घोषणा

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

मंडल मुरादाबाद/ जिला अमरोहा उत तहसील हसनपुर के ग्राम मुबारकपुर कला अल अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज के मैदान में बहुजन समाज पार्टी का एक आज महासम्मेलन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का आह्वान किया और बताया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही जब बसपा का शासन काल था तो अधिकारी भी समय पर अपनी ड्यूटी निभाते थे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी हुई थी आज वर्तमान सरकार में व्यापारी परेशान नौजवान परेशान महंगाई की मार जनता झेल रही है भाजपा सरकार अपने जुमले की सरकार है किसान खुदकुशी करने को तैयार है किसान को खाद नहीं मिल रहा महंगाई दर-दर बढ़ती जा रही है और पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली ने कहा की 2014 में भाजपा के नेताओं का विदेशों में काला धन लाने की बात कर रही थी आज 4 गुना हो चुका है जांच करा ले भाजपा सरकार के सभी भ्रष्ट मिलेंगे और मैं आप सब जनता से अपील करता हूं मेरी माताओ और बहनों मैं एक बड़ा पैगाम लेकर आया हूं तहसील हसनपुर की ग्राम मुबारकपुर कला अल अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज में आज एक पैगाम दे रहा हूं जो बहन कुमारी मायावती ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी वह आपके सामने मैं जिम्मेदारी सौंप रहा हूं आने वाले 2027 के चुनाव में हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टो साहब को हसनपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर रहा हूं और यह पैगाम बहन कुमारी मायावती जी ने भेजा है मैं आपसे विनती करता हूं की आने वाले 2027 के चुनाव में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हसनपुर विधानसभा से हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टो को प्रत्याशी भारी मतों से जीता कर विधानसभा भेजना है बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली ने भाजपा सरकार पर जाम का निशान सादा इस बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे

डिजिटल ई-रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

लोकतंत्र की शान/ सतीश चंद राणा

तहसील बार एसोसिएशन हसनपुर ने प्रदेश सरकार की प्रस्तावित डिजिटल ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप निबंधक कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया। अधिवक्ताओं ने योजना को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए इसे जनहित और रोजगार के लिए नुकसानदायक बताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह एवं महासचिव ब्रजकिशोर एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री कार्यों को निजी कंपनियों के माध्यम से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि इससे दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता, मुंशी, टाइपिस्ट तथा रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा।

गौ रक्षा प्रकरण में 14 गौ रक्षकों को उम्रकैदः राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने फैसले का किया कड़ा विरोध, देशव्यापी ज्ञापन अभियान की घोषणा

लोकतंत्र की शान/ व्यूरो अवनीत कुमार शर्मा

लखनऊ। राजधानी/मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में चर्चित गौ रक्षा संघर्ष प्रकरण में अदालत द्वारा 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रीय युवा वाहिनी एवं राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा ने इस निर्णय का कड़ा विरोध व्यक्त किया है।क्या है मामला?जानकारी के अनुसार कई वर्ष पूर्व कथित गौ तस्करी का विरोध करने के दौरान गौ रक्षकों और तस्करों के बीच संघर्ष हुआ था। घटना के बाद हिंसा एवं आगजनी के आरोपों में पुलिस ने 114 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। हाल ही में न्यायालय ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा आर्थिक दंड भी लगाया है। अन्य आरोपियों के मामलों पर न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

मोहर्रम को लेकर बरेली में हाई अलर्टः 44 जोन, 158 सेक्टर में सुरक्षा चक्र, ड्रोन और सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

लोकतंत्र की शान

बरेली (उत्तर प्रदेश) | संदीप चंद्राः मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए बरेली प्रशासन ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत कर दिया है। जिले में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए तकनीक और मानव संसाधनों का संयुक्त उपयोग किया जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, अव्यवस्था या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर तत्काल और कठोर कार्रवाई होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहर्रम के दौरान पूरे जिले को सुरक्षा दृष्टि से 44 जोन और 158 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है, जिससे किसी भी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।

सुरक्षा के लिए जमीन से आसमान तक निगरानी-इस बार सुरक्षा व्यवस्था केवल पुलिस बल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा। जुलूस मार्गों, ताजिया स्थलों और कर्बला क्षेत्रों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष मॉनिटरिंग टीम सक्रिय रहेगी ताकि किसी भी भ्रामक पोस्ट, वीडियो या अफवाह को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत संवेदनशील हो जाती है, इसलिए डिजिटल निगरानी को भी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बनाया गया है।

चार जिलों में निकाले जाएंगे 1384 जुलूस-पुलिस उपमहानिरीक्षक अजय साहनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बरेली परिक्षेत्र के चार जिलों—बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर—में कुल 1384 मोहर्रम जुलूस प्रस्तावित हैं। इन जिलों में 2128 ताजियों की स्थापना की जाएगी, जबकि 2003 ताजियों को कर्बलाओं में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन टेस्ट (PAT) 2023-24 की मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अलग-अलग छात्र संगठनों ने मेरिट लिस्ट में धांधली, रोस्टर नियमों के उल्लंघन और गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। आज विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में संयुक्त छात्र संगठनों की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र नेताओं ने कहा कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई, तो चरणबद्ध आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छात्र नेता डॉ. चंदन यादव ने आरोप लगाया कि PAT 2023-24 की मेरिट लिस्ट तैयार करने में रोस्टर नियमावली की अनदेखी की गई है और मेधावी छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने चहेतों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया। यह मेधा और पारदर्शिता दोनों के साथ धोखा है। उन्होंने बताया कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था। उस दौरान कुलपति ने एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन चार सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण पूरे मामले की बिंदुवार शिकायत लोकभवन को भी भेजी गई है। छात्र नेताओं ने घोषणा की कि 20 जून को बड़ी संख्या में छात्र लंगट सिंह कॉलेज गेट से कुलपति आवास तक मशाल जुलूस निकालेंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल मेरिट लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और मेधा के सम्मान की लड़ाई है। इतिहास विभाग के गोल्ड मेडलिस्ट अभिषेक कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि कुलपति ने जांच के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन तीन सप्ताह से अधिक गुजरने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभिषेक ने इंटरव्यू प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अभ्यर्थियों को पक्षपातपूर्ण तरीके से अधिक अंक दिए गए, जबकि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद उन्हें अपेक्षाकृत कम अंक देकर मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। भूगोल विभाग के गोल्ड मेडलिस्ट अविनाश कुमार ने भी चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर PAT 2023-24 की मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया। उनके अनुसार इंटरव्यू और मूल्यांकन प्रक्रिया में पक्षपात करते हुए कुछ अभ्यर्थियों को अधिक अंक देकर चयनित किया गया। प्रेस वार्ता में छात्र लोजपा विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन पासवान, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के अभिषेक कुशवाहा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार, समीर झा, नीरज कुमार समेत विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मेरिट लिस्ट की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

कांटी में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान

लोकतंत्र की शान : कांटी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-मोतिहारी रेल खंड पर कांटी के कपरपुरा स्टेशन के पास श्रीसियां में बुधवार को एक सुसाइड करने की घटना सामने आई। एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके से रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। बरामद सुसाइड नोट में मृतक युवक ने अपनी पत्नी की बेवफाई का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान था। इसी गहरे सदमे और तनाव के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का निर्णय लिया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी अभय कुमार के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार, उसकी शादी पिछले साल 2025 ही हुई थी। घटना के वक्त युवक ने सफेद शर्ट और जींस पहनी हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची। घटना की सूचना कांटी थाना को भी दी गई। पुलिस ने जांच किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया। परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। कांटी थाना प्रभारी रविकांत पाठक ने बताया कि मृतक की पहचान कर ली गई है और उसके परिजनों को सूचित किया गया था, पोस्मार्टम से इनकार करने पर परिजन शव सौंप दिया गया है। घटना स्थल से सुसाइड नोट मिलने से प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजन के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वैशाली में किन्नर से डेढ़ करोड़ की चोरी

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली के सदर थाना क्षेत्र में 12 मई की शाम एक ट्रांसजेंडर से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण और 8.75 लाख रुपये नकद चोरी हो गए। यह घटना स्टेशन रोड पर रेल कोच रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के बीच हुई। पुलिस कार्रवाई में देरी के विरोध में सैकड़ों किन्नरों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित ट्रांसजेंडर सपना कुमारी ने सदर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर रात वह अपने ड्राइवर सौरभ कुमार के साथ अपनी एक्सयूवी कार से पटना से महुआ लौट रही थीं। स्टेशन रोड पर रेल कोच रेस्टोरेंट के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी चलती गाड़ी के रेडिएटर के पास कुछ फेंका। गाड़ी करीब 10 मीटर आगे बढ़ी ही थी कि एक दूसरे अज्ञात व्यक्ति ने इशारा कर गाड़ी से धुआं निकलने की बात कही। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। धुआं निकलने की बात सुनकर सपना कुमारी और ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरे। उन्हें गाड़ी के अंदर दम घुटने जैसा महसूस हुआ। वे गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी कर उसका बोनट खोलकर देखने लगे। इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर बदमाशों ने गाड़ी की बीच वाली सीट पर रखे गहने और रुपयों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए गहने और रुपये किन्नर समाज के थे, जो उन्हें शगुन के रूप में मिले थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। मामले में अपेक्षित पुलिस कार्रवाई न होने से किन्नर समाज में रोष है, जिसके चलते सैकड़ों किन्नरों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार का अल्कोहल जांच, हाजीपुर में ब्रेथ एनलाइजर लेकर आधी रात पहुंची पुलिस

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर (वैशाली)। हाजीपुर में शराबबंदी कानून के तहत एक पत्रकार के घर पर हुई छापेमारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार देर रात उत्पाद विभाग और नगर थाना पुलिस ने दैनिक अखबार 'अहान' के संपादक मनीष कुमार सिंह के राजेंद्र चौक स्थित किराए के मकान पर छापा मारा। ब्रेथ एनालाइजर जांच में पत्रकार में अल्कोहल की मात्रा शून्य पाई गई। यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई, जब पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पांच गाड़ियों से मौके पर पहुंची। पत्रकार मनीष कुमार सिंह ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य सो रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार में किसी ने कभी नशा नहीं किया, फिर भी उनकी पत्नी और बच्चों के सामने पूरे घर की तलाशी ली गई। पत्रकार ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वीडियो में एक महिला कांस्टेबल पत्रकार से ब्रेथ एनालाइजर पर सांस फुंकवाती दिख रही है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 'नील' दर्ज हुई। रिपोर्ट शून्य आने के बाद एक महिला अधिकारी ने सिविल ड्रेस में मौजूद एक युवक को इशारा किया, जिस पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने उन्हें फटकार लगाई। दोनों अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। मनीष कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई प्रशासन के भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करने के प्रतिशोध में की गई है। स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस अब सड़कों के बजाय घरों में सो रहे लोगों की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हाजीपुर के राजेंद्र चौक और उत्पाद विभाग कार्यालय के पास नालों की सफाई के दौरान अक्सर बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें मिलती हैं, लेकिन उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती।

दफादार-चौकीदार मांगों के लिए प्रदर्शन पर उतरे

डाकबंगला चौराहा होते सीएम आवास मार्च करने की तैयारी, पुलिस ने की बैरिकेडिंग

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना में आज बिहार भर से पहुंचे हजारों दफादार-चौकीदार मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से जेपी गोलंबर, डाकबंगला चौराहा होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की तैयारी में हैं। संभावित भीड़ और कानून-व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने गांधी मैदान, जेपी गोलंबर और डाकबंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है।

पहले भी हुआ था लाठीचार्जः इससे पहले फरवरी में चौकीदार-दफादारों ने डाकबंगला चौराहे की बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने पर लाठीचार्ज किया गया था। उस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, जबकि एक आंदोलनकारी के गंभीर रूप से जख्मी होने की भी सूचना सामने आई थी।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमतिः पिछले प्रदर्शनों के दौरान हंगामा को देखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गांधी मैदान से लेकर सीएम हाउस जाने वाले पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अनुमति है, लेकिन किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

बिहार के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी होने के कारण प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हो रही है। वहीं, पटना समेत दक्षिण बिहार के कई इलाके तेज धूप और भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50Kmph की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना है। उधर, अररिया में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। 42 डिग्री के साथ कैमूर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। 8 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा।

8 जिलों का तापमान 40°C पारः छपरा, पटना, औरंगाबाद, शेखपुरा, गया, रोहतास, बक्सर, कैमूर में बुधवार को पारा 40°C से ज्यादा रहा। कैमूर में 42.1°C, बक्सर में 41.5°C तापमान दर्ज किया गया।

19 जून से पूरे बिहार में बिगड़ सकता है मौसमः मौसम विभाग के अनुसार, 19 जून से पूरे बिहार में मौसम का असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। उत्तर बिहार के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

सोशल मीडिया पर बढ़ते रिश्तों में ठगी का खतरा, युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन रिश्तों में ठगी और धोखे के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां युवाओं को फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से भावनात्मक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार बनाया गया। ऐसा ही एक मामला अभिषेक नामक युवक से जुड़ा है, जो बिहार के एक छोटे कस्बे का निवासी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय अभिषेक की मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से हुई। आकर्षक प्रोफाइल और प्रभावशाली बातचीत के चलते दोनों के बीच निकटता बढ़ती गई। कुछ ही महीनों में यह रिश्ता भावनात्मक रूप से गहरा हो गया। बताया जाता है कि दोनों के बीच नियमित बातचीत, वीडियो कॉल और भविष्य की योजनाओं ने अभिषेक का भरोसा पूरी तरह जीत लिया। हालांकि, जब अभिषेक ने रिया से मिलने की इच्छा जताई, तो हर बार किसी न किसी बहाने से मुलाकात टाल दी गई, जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी दौरान रिया ने आर्थिक परेशानी का हवाला देकर अभिषेक से कई बार पैसे की मांग की, जिसे उसने बिना सत्यापन किए भेज दिया। कुछ समय बाद अचानक रिया का संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया। बाद में जानकारी मिली कि संबंधित प्रोफाइल फर्जी थी और कई अन्य लोग भी इसी प्रकार की ठगी का शिकार हो चुके थे। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर बने रिश्तों में सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी ऑनलाइन संबंध में विश्वास करने से पहले व्यक्ति की वास्तविक पहचान और उसके व्यवहार की पुष्टि करना जरूरी है। जिला प्रशासन और साइबर विशेषज्ञों ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सावधानीपूर्वक बातचीत करें और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त अभियान, 18 ट्रकों सहित कई वाहनों पर कार्रवाई

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं जिला पदाधिकारी सहरसा श्री दीपेश कुमार के निर्देश के आलोक में जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106, 107 एवं 327E, वैद्यनाथपुर रोड तथा गंडौल-बिरौल सड़क पर बलुआहा पुल के समीप जिला परिवहन कार्यालय द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों की सघन जांच की गई। सड़क किनारे खड़े ट्रकों एवं अन्य भारी वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18 ट्रकों का चालान किया गया। संबंधित वाहन चालकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने वाहनों की पार्किंग केवल स्वीकृत ले-बाई (Lay-by), वे-साइड एमेनिटीज (Wayside Amenities), पेट्रोल पंप, धर्मकांटा अथवा अन्य निर्धारित स्थलों पर ही करें। जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा यातायात संचालन बाधित होता है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर लंबे समय से खड़े वाहनों को जब्त कर संबंधित थाना में जमा कराया जाएगा। विशेष जांच अभियान के दौरान बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो रिक्शा एवं अन्य वाहन चलाते पाए गए चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। ऐसे चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार अर्थदंड लगाया गया।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर दिए गए सख्त निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आज जिला जल एवं स्वच्छता समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में जल एवं स्वच्छता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन डोर-टू-डोर भ्रमण कर अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी अक्रियाशील इकाइयों को यथाशीघ्र चालू करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही साफ-सफाई कार्यों में प्रयुक्त मरम्मती योग्य उपकरणों को तत्काल ठीक कराने तथा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय सुविधा के साथ उत्कृष्ट साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जीविका दीदियों को स्वच्छता व्यवस्था में मोबिलाइजर के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया, ताकि जनसहभागिता के माध्यम से स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री पुलक कुमार, सिविल सर्जन सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

'सुरक्षा घटाने-आवास का फैसला सुरक्षा समिति का, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं', लालू के आरोपों पर अशोक चौधरी का पलटवार

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास और सुरक्षा घटाने के विवाद पर राजनीति तेज हो गई है। बीते कल RJD सुप्रीमो लालू यादव ने मीडियो को दिए बयान में कहा था कि, 'सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं।' इस बयान पर जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, 'लालू जी मेंटली गड़बड़ा गए हैं। जब तक नीतीश कुमार सत्ता ने थे, तो आप राबड़ी आवास में रहे। अब जब सरकार ने आपको एक व्यवस्थित जगह अलग से दे दिया है, तब आप जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं कि सब नीतीशवे करवा रहा है।' सुरक्षा घटाने के आरोपों और जवानों को लौटाने के सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि, 'सुरक्षा और आवास का सभी निर्णय तो सुरक्षा समिति और पुलिस विभाग करती है न। इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है।' राबड़ी आवास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "हां, हमारी सुरक्षा हटा ली गई है। सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं।" इससे पहले सिंगापुर से लौटने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर उन्होंने कहा था, "सब पागल हो गए हैं। घृणा कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता।"

वहीं बंगला विवाद और सुरक्षा में कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी बदला ले रहे हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस ने x पर पोस्ट कर जानकारी दी हैं। यह बयान बिहार पुलिस ने तब दिया हैं, जब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में कटौती के बाद अपनी पूरी सुरक्षा लौटा दी थी। बिहार पुलिस ने कहा है कि दोनों माननीय को सुरक्षा सरकार के तरफ़ से प्रदान की गई है। दोनों नेताओं को वर्तमान में विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के अनुसार सुरक्षा प्रदान किया गया है, जिसमें अंगरक्षक/ आवास गार्ड/ स्कॉट गार्ड/ पायलट के अतिरिक्त BR Car भी उपलब्ध कराया गया है। रविवार रात लालू यादव के साथ उनकी बेटी और सांसद Misa Bharti भी मौजूद थीं। बंगला खाली करने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हम 15 दिन के अंदर बंगला खाली कर देंगे।" वहीं, लालू परिवार की सुरक्षा घटाए जाने के मुद्दे पर मीसा भारती ने कहा, "लालू जी और राबड़ी जी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लालू-राबड़ी के साथ उनके चाहने वाले बहुत हैं। मैं भी अपनी सुरक्षा लौटा रही हूं।" इधर, बीते रविवार को राबड़ी देवी पटना के कौटिल्य नगर स्थित घर का कामकाज देखने पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि सरकारी आवास खाली करने के बाद लालू परिवार इसी घर में शिफ्ट होगा।

विवाद बंगला खाली करने के नोटिस से शुरू हुआः 29 मई को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए तीसरा नोटिस दिया। दिल्ली से पटना लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा, '10, सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी अभी नए-नए मुख्यमंत्री बने हैं।

CM बोले- बंगला खाली होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकताः मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा। पक्का खाली होगा। धरती पर कोई रोक नहीं सकता है। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। कोई राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है। मां को अलग घर चाहिए। बेटे को अलग घर चाहिए। मां-बेटे और पति को अलग-अलग सुरक्षा चाहिए। बिहार में हरा गमछा, हरा गमछा शांति का प्रतीक है। जो गुंडागर्दी करेगा उसे तो जेल में डालेंगे ही ना। जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए एक ही जगह है मुजफ्फरपुर की जेल।' CM सम्राट चौधरी ने कहा, बंगला किसी की बपौती नहीं है। लोगों को बंगले से मोह हो गया है। बेटे को अलग घर चाहिए, मां को अलग घर चाहिए। मैं जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने कहा, आप बाहर लिखवा दीजिए ये लोकसेवक का आवास है।

बिहटा प्रखंड परिसर में नए भवन का निर्माण कार्य शुरू, पुराने भवनों पर चला बुलडोजर

लोकतंत्र की शान , पटना

❒ **बनेगा नया आधुनिक प्रखंड मुख्यालय और आवासीय परिसर**

पटना जिले के बिहटा प्रखंड परिसर में नए प्रखंड कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण की दिशा में काम शुरू हो गया है। गुरुवार से परिसर में मौजूद पुराने सरकारी भवनों को जेसीबी और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, जिन भवनों को हटाया जा रहा है वे करीब 50 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं। इन्हें हटाकर यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया प्रखंड मुख्यालय, सभागार और सरकारी आवासीय परिसर विकसित किया जाएगा।

प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने की तैयारीः चल रहे कार्य का निरीक्षण करने के लिए बिहटा के प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवजन्म राम स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य को तय मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक, प्रखंड परिसर में मौजूद कई पुराने भवन लंबे समय से अनुपयोगी हो चुके थे। स्थानीय स्तर पर यह भी रिपोर्ट दी गई थी कि कुछ भवनों का उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद भवनों को हटाने और नए निर्माण की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से नए प्रखंड मुख्यालय और सभागार के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि परिसर में मौजूद लगभग 10 पुराने सरकारी भवनों को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। इसके बाद इसी स्थान पर नया प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा।

नई इमारत में होंगी आधुनिक सुविधाएंः अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा प्रखंड कार्यालय काफी पुराना हो चुका था और कामकाज में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। नए भवन में आधुनिक प्रशासनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे आम लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलेगी।

प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में हुए टेंडर घोटाला का मास्टरमाइंड और ठेकेदार रिशु श्री बेहद शातिर है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) की टीम को उसका शातिराना अंदाज देखने को मिला है। वो भी उस दौरान जब रिशु श्री 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। सूत्रों के मुताबिक, बेउर जेल से बाहर आने के बाद उसका तौर तरीका बदला हुआ मिला।

उसके हाव-भाव पूरी तरह से बदले गए हैं। जब टीम ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह शुरुआत में सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। बार-बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। उसे फंसाया गया है। सवाल पूछे जाने पर गोलमोल बातें कर घूमा रहा था। पूछताछ के दौरान रिशु श्री ने यहां तक कह दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। फर्जी तरीके से बनाई गई है। इसके आधार पर SVU ने जो FIR दर्ज की है, वो भी सही नहीं है। मतलब, वह जांच एजेंसियों के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहा था। जब SVU ने उसे गिरफ्तार किया था, तब उस वक्त की पूछताछ में वो सारे सवालों का जवाब सही तरीके से दे रहा था।

संक्षिप्त समाचार

जनजातीय छात्रावास बनेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पोषण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के केंद्र

छात्र हित सर्वोपरि, छात्रावासों के संसाधनों का उपयोग केवल विद्यार्थियों के लिए हो : कलेक्टर विकास मिश्रा

(ऋचा पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं छात्र-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा ने छात्रावास अधीक्षकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, अधोसंरचना तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रावासों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि और संसाधनों का उपयोग केवल विद्यार्थियों के हित एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए किया जाए। कलेक्टर ने कन्या छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं में विशेष सुधार लाने, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने तथा सभी छात्रावास परिसरों में पोषण वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने, समय पर पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध कराने तथा छात्रावासों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि आवश्यक सामग्री की खरीद स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर की जाए, जिससे स्थानीय महिला समूहों को रोजगार के अवसर मिल सकें। साथ ही विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र समय-सीमा में तैयार करने तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के चिन्हांकन कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने छात्रावासों में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए छात्र समितियों के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर नागौर पुलिस की सख्त कार्रवाई,

» गोटन व जायल में डीजे सहित दो पिकअप वाहन जब्त

» ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अभियान जारी

लोकतंत्र की शान , मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। नागौर जिले में तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ASP नागौर आशा राम चौधरी के निर्देशन में जिलेभर में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को गोटन और जायल थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाने पर दो डीजे सिस्टम एवं उन्हें ले जा रहे पिकअप वाहनों को जब्त किया। पुलिस के अनुसार गोटन थाना क्षेत्र में टालनपुर रोड पर एक पिकअप वाहन में लगे डीजे को अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए डीजे सहित पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। इसी प्रकार जायल कस्बे में थाना परिसर के सामने ही एक पिकअप वाहन में लगे डीजे को तेज आवाज में बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजे और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से भी अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि में डीजे अथवा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करें तथा कानून का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें।

पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया तहसील का संग्रह अमीन, एंटी करप्शन टीम ने कैंटीन में बिछाया जाल

NPS खाते से प्लॉट खरीदने के लिए मांगी घूस, शिकायत पर हुई कार्रवाई – भ्रष्टाचार पर बड़ा वार

लोकतंत्र की शान ,(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन संगठन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील सदर में तैनात एक संग्रह अमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी कर्मचारी पर आरोप है कि उसने एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) खाते से भूखंड खरीदने के लिए धन निकासी से संबंधित आवेदन को आगे बढ़ाने और रिपोर्ट लगाने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अधिकारियों के अनुसार आरोपी की पहचान जोरावर सिंह (55 वर्ष) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में तहसील सदर बरेली में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत है। आरोपी मूल रूप से थाना भुता क्षेत्र के अमलोनीपुर गांव का निवासी बताया गया है।

शिकायत के बाद शुरू हुई निगरानी-इस मामले की शुरुआत तब हुई जब शिकायतकर्ता सुरेश चन्द्र, निवासी सम्राट अशोक नगर, नवादा जोगिया ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से संपर्क किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने एनपीएस खाते से प्लॉट खरीदने के उद्देश्य से धन निकासी के लिए आवेदन किया था, लेकिन संबंधित फाइल पर रिपोर्ट लगाने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के एवज में संग्रह अमीन द्वारा पांच हजार रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले की प्राथमिक जांच की। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद अधिकारियों ने ट्रैप कार्रवाई की योजना तैयार की।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम 'खंडूरी एयरपोर्ट' करने की उठी मांग

मानवाधिकार महिला जनकल्याण सुरक्षा आयोग के मंत्री महताब ख़ान चांद ने प्रधानमंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र

लोकतंत्र की शान : खिज़र अहमद , नजीबाबाद। मानवाधिकार महिला जनकल्याण सुरक्षा आयोग के मंत्री महताब ख़ान चांद ने देवभूमि उत्तराखंड स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को प्रेषित मांग पत्र में कहा है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम "खंडूरी एयरपोर्ट" रखा जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महताब ख़ान चांद ने कहा कि स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी ने भारतीय सेना में उल्लेखनीय सेवाएं देने के साथ-साथ देश के सड़क एवं आधारभूत ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार तथा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे देश के विकास को नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के विकास, जनसेवा तथा राष्ट्र निर्माण में दिए गए उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक स्मरणीय बनाए रखने के लिए जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा जाना उचित होगा। इससे उनके उत्कृष्ट कार्यों को स्थायी सम्मान मिलने के साथ-साथ देशवासियों को भी प्रेरणा मिलेगी। महताब ख़ान चांद ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।

पालना गृह में सुरक्षा व्यवस्था फेल, डीएलएसए सचिव का सख्त एक्शन

कई संस्थानों में सुधार के निर्देश

लोकतंत्र की शान

नागौर/मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता की अध्यक्ष तारा अग्रवाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के सचिव संजय कुमार मालवीया ने गुरुवार को नागौर स्थित विभिन्न संस्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर गंभीर कमियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत पुराने अस्पताल परिसर स्थित पालना गृह से की गई। यहां अलार्म सिस्टम की जांच के दौरान यह पूरी तरह बंद मिला। परिसर में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी तथा कई स्थानों पर गंदगी पाई गई। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं में भी कमियां मिलने पर सचिव मालवीया ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को निर्देश दिए कि पालना गृह की सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, अलार्म सिस्टम तत्काल चालू कराया जाए तथा सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पालना गृह जैसे संवेदनशील संस्थानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद सचिव ने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का निरीक्षण किया। यहां कार्मिकों की ड्यूटी व्यवस्था एवं प्रबंधन में अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर, नागौर के निरीक्षण के दौरान भी कार्मिक प्रबंधन एवं ड्यूटी व्यवस्था में कमियां मिलीं। इस पर सचिव ने केंद्र की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिला कारागृह, नागौर का भी निरीक्षण किया गया। सचिव मालवीया ने बंदियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, विधिक सहायता क्लिनिक एवं डिस्पेंसरी का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान से बाहर के बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी। इसके पश्चात उन्होंने राठौड़ी कुआं स्थित अपना घर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा संस्थान प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सचिव मालवीया ने कहा कि आमजन, महिलाओं, बच्चों, बंदियों एवं वृद्धजनों से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा, स्वच्छता और पारदर्शी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को शीघ्र दूर कर संस्थानों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

बच्चों का सुरक्षित बचपन ही उज्ज्वल भविष्य की नींव : विधायक रीती पाठक

पॉक्सो एक्ट एवं बाल संरक्षण विषय पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायक और कलेक्टर ने किया संबोधित

(ऋचा पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला प्रशासन सीधी द्वारा संचालित 'जागृति अभियान' के अंतर्गत टाटा कॉलेज सीधी में पॉक्सो एक्ट एवं बाल संरक्षण विषय पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रीती पाठक एवं कलेक्टर विकास मिश्रा ने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। विधायक रीती पाठक ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन ही उनके उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या प्रशासन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माता-पिता को बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए तथा उनकी गतिविधियों पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विद्यालयों और छात्रावासों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों के नियमित चरित्र सत्यापन की आवश्यकता भी बताई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि कई बच्चे विभिन्न कारणों से अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाते। ऐसे में शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के साथ विश्वास का संबंध स्थापित करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकारों, हेल्पलाइन सेवाओं तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी जानी चाहिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिलेः विश्वामित्र

» जनपद पंचायत प्रांगण में खंडस्तरीय शिविर आयोजित

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जनपद पंचायत सिहावल में जन कल्याण शिविर सह हितलाभ वितरण का समापन कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक विश्वामित्र पाठक के मुख्य आतिथ्य एवं सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा की विशेष उपस्थिति में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजेश शुक्ला एसडीएम ने आयोजित तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उनके निराकरण के बारे में अवगत कराया। जनपद स्तरीय शिविर की नोडल अधिकारी दीप्ति वनवासी ने शिविर के संचालन, आवेदन पत्रों के पंजीयन से लेकर निराकरण की प्रक्रिया एवं हितलाभ वितरण के बारे में जानकारी दी। शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं, प्राप्त आवेदन पत्रों एवं निराकरण से अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वामित्र पाठक विधायक विधानसभा क्षेत्र सिहावल ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि जनकल्याण शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बहरी आगमन के दौरान मेरें मांग पर मुख्यमंत्री ने जन कल्याण शिविर आयोजित कराकर समस्याओं के निराकरण कराने की घोषणा की थी उसी के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि ने उपस्थित लोगों से जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पात्रतानुसार लाभ लेने की अपील की ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मुख्य अतिथि ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद एवं विधायक ने किसानों को बीज का वितरण किया तथा विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं केसीसी, आयुष्मान कार्ड, अनुग्रह राशि, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल कार्ड, पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत पत्र वितरित किए।।

नायब तहसीलदार पर पद के दुरुपयोग का आरोप

आयुक्त रीवा से की गई शिकायत

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के सुभाष नगर बनिया कॉलोनी निवासी अरुण कुमार गुप्ता ने तहसील देवसर, जिला सिंगरौली में पदस्थ नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह पर पद के दुरुपयोग और अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगाते हुए रीवा संभाग के आयुक्त को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार 14 जून 2026 को नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह ने कथित रूप से अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए देवसर से बिना नंबर का ट्रैक्टर, बोरिंग मशीन और मजदूर बुलाकर सीधी स्थित शिकायतकर्ता की भूमि पर पहुंचकर फेंसिंग दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नलकूप खनन कराने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह कार्रवाई कलेक्टर सीधी द्वारा जारी आदेशों के विपरीत की गई।

अरुण कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो नायब तहसीलदार के पुत्र अक्षत सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की धमकी दी। मामले की सूचना कोतवाली थाना सीधी में दी गई, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरे घटनाक्रम के मुख्य साजिशकर्ता नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया, जबकि घटना उनके निर्देशन में हुई। आयुक्त रीवा को दिए गए आवेदन में शिकायतकर्ता ने कहा है कि एक राजस्व अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर निजी भूमि विवाद में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है। उन्होंने आशंका जताई है कि आरोपी अधिकारी अपने प्रभाव का उपयोग कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उन्हें न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शिकायत के साथ कलेक्टर सीधी के आदेश की प्रति, एफआईआर की प्रति तथा घटनास्थल का वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह की भूमिका की जांच की जाए तथा पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया जाए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रीवा संभाग प्रशासन इस गंभीर शिकायत को किस स्तर पर संज्ञान में लेकर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

मेड़ता रोड रेलवे का अतिक्रमण पर बड़ा एक्शनः सर्कुलेटिंग एरिया में चला पीला पंजा

» मंदिर व दुकानों के बाहर हटाए कब्जे, व्यापारियों ने पक्षपात का लगाया आरोप

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड, एजाज़ अहमद उस्मानी। मेड़ता रोड रेलवे प्रशासन ने रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गुरुवार को व्यापक अभियान चलाते हुए सर्कुलेटिंग एरिया सहित रेलवे परिसर के विभिन्न हिस्सों में जेसीबी (पीला पंजा) चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाए। इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर तथा कई दुकानों के सामने किए गए अस्थायी निर्माण, टीनशेड, चबूतरे, ठेले, स्टॉल और अन्य अवरोधों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और कुछ व्यापारियों तथा स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। सुबह से शुरू हुए इस अभियान में रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और राजस्थान पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी मशीनों की सहायता से रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल भी रहा तथा लोगों की भीड़ जमा हो गई। रेलवे प्रशासन का कहना है कि रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। वाहनों की पार्किंग, यातायात व्यवस्था और स्टेशन परिसर की सुरक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यह अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रेलवे की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों और व्यापारियों ने रेलवे प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कई स्थानों पर वर्षों से अतिक्रमण मौजूद है, लेकिन कार्रवाई केवल चुनिंदा दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर की गई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो वह सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कार्रवाई के दौरान मंदिर परिसर के बाहर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने पर कुछ स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभियान किसी व्यक्ति, संस्था या धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि केवल रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। रेलवे की संपत्ति पर किए गए सभी अवैध कब्जों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। कार्रवाई पूरी होने के बाद रेलवे प्रशासन ने आमजन से रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने, स्टेशन परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने तथा रेलवे के नियमों का पालन करने की अपील की। रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिए कि भविष्य में भी समय-समय पर ऐसे अभियान चलाकर रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

अभिनव अग्रवाल एडवोकेट को मिली नई संगठनात्मक जिम्मेदारी, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव बने

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी बधाई, आलाकमान का जताया आभार

लोकतंत्र की शान/ खिज़र अहमद

नजीबाबाद। युवा कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला एवं प्रदेश प्रभारी विशाल चौधरी द्वारा स्थानीय निवासी अभिनव अग्रवाल एडवोकेट को युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति संगठन को मजबूत करने तथा आगामी चुनावों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अपनी नियुक्ति पर अभिनव अग्रवाल एडवोकेट ने युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने के साथ-साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिनव अग्रवाल की संगठनात्मक क्षमता और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ से प्रदेश में युवा कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि अभिनव अग्रवाल वर्ष 2009 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

कुछ लोग गाय का दूध पिएंगे और सड़क पर छोड़ देंगे, जब वह फसल का नुकसान करेगी तो दोष मुझे देंगेः सीएम योगी

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग गाय का दूध पिएंगे, फिर उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ देंगे और जब ये गाय फसलों का नुकसान करेंगी तो दोष मुझे देंगे। हमारा संकल्प व संस्कार है कि गोमाता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने सिख गुरुओं के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कोई आक्रांता या कसाई गोहत्या करता था, तो सिख वीर उसका वहीं काम तमाम कर देते थे। यह उस कालखंड की बात है, जब देश गुलाम था और लोग विदेशी आक्रांताओं के साये में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कानपुर में आयोजित 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला-2026' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा, जो गोमाता की उपासना न करता हो, उसे अपने जीवन व परिवार का हिस्सा न मानता हो। गोमाता आधारित खेती न केवल कृषि को सशक्त बनाती है, बल्कि गोमाता की रक्षा भी करती है। साथ ही, यह हम सभी को पुण्य का भागीदार भी बनाती है।

कटनी महिला कांग्रेस द्वारा पुतला दहन विरोध प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यौरे चीफ़ जबलपुर कटनी मध्यप्रदेश

कटनी : विगत दिनो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आदेशानुसार पर एवं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोसी सेतिया जी के निर्देशन में कटनी जिले में प्रदेश महासचिव एवं शहर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनी वर्मा जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा सुश्री मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन को अवैधानिक रूप से निरस्त किए जाने के विरोध में चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार का थाना तिराहा में पुतला दहन किया गया। महिला अध्यक्ष रजनी वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग आज सत्ता पक्ष की कठपुतली बना बैठा है और सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा लगातार महिला विरोधी और जनता विरोधी कार्यों को कर रही है, एक तरफ भाजपा नारी सम्मान की बात करती है तो दूसरी तरफ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाजपा की यह दोहरी मानसिकता और जनता को भ्रमित करते हुए महिला विरोधी कार्यों का जीता जागता उदाहरण सुश्री मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा में नामांकन रद्द होना देखा जा सकता है जहां एक और किसी भी नामांकन में कोई कमी होने पर हर दावेदार को उस कमी को सुधारने का मौका और समय दिया जाता है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी रही मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फार्म को बिना कोई समय दिए चुनाव आयोग द्वारा यह कहकर निरस्त किया गया कि उनके द्वारा कुछ जानकारी छुपाई गई और जिस जानकारी की बात की गई वह भी गलत थी, मीनाक्षी नटराजन जी को यह कहा गया कि उनके द्वारा नामांकन फार्म में FIR में उनका नाम होने का जिक्र छुपाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट या फिर प्रकरण थाने में दर्ज ही नहीं था केवल जिस FIR की बात की गई उसमें पीड़िता द्वारा यह कहा गया था की उन्होंने संबंधित विषय की जानकारी मीनाक्षी जी को दी थी जो कि उस समय वहां की तात्कालिक प्रभारी थी, यह घटना तेलंगाना की थी.. बिना तथ्य की जानकारी लिए चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार के द्वारा मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को रद्द करना सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या थी जिसका अधिकार संविधान किसी को भी नहीं देता। भाजपा लगातार महिला विरोधी और जनता के हित विरोध का काम करती जा रही है, और विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर इसका विरोध करती रहेगी। इसके साथ ही महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एसडीएम के हाथों ज्ञापन सोपा जिसमें यह अनुरोध किया की एक महिला होने के नाते राज्यपाल महोदया मीनाक्षी नटराजन जी के साथ हुए इस अन्याय का संज्ञान लेते हुए न्याय करें।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में विपक्षी सांसदों ने संवैधानिक निकायों में सरकारी हस्तक्षेप पर जताई आपत्ति

काठमांडू। नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में विपक्षी सदस्यों ने संवैधानिक निकायों में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति जताते हुए संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने कहा कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होता और उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रतिनिधि सभा की बैठक गुरुवार को शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया और सीमा संबंधी मुद्दों पर प्रधानमंत्री के बयान को संसदीय अभिलेख से हटाने की मांग दोहराई। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर डीपी अर्याल ने सीपीएन (यूएमएल) के सदस्य नरेंद्र कुमार केरूंग को सदन में बोलने की अनुमति दी। केरुंग ने उन खबरों पर सवाल उठाया जिनमें कहा गया था कि संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बुलाया गया और उन्हें पूछताछ, हिरासत या गिरफ्तारी की धमकी दी गई। उन्होंने सरकार से इस विषय पर जवाब देने की मांग की और प्रधानमंत्री से सीमा विवाद के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसी तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सांसद लक्ष्मी पोखरेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान और वित्त मंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई कथित धमकीपूर्ण भाषा सरकार के लिए हितकर नहीं होगी। उन्होंने उन कार्रवाइयों पर भी आपत्ति जताई जिन्हें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को डराने एवं उनका अपमान करने वाला बताया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रमेश मल्ल ने चेतावनी दी कि सरकार के हालिया कदम देश के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। उन्होंने संवैधानिक निकायों के प्रमुखों को पूछताछ के लिए बुलाने और उनके खिलाफ संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई की खबरों को गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच की मांग की।

ई-पासपोर्ट खरीद प्रक्रिया में नेपाल की पूर्व विदेश मंत्री आरजू देउवा भी जांच के दायरे में

काठमांडू। नेपाल के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले वर्ष की ई-पासपोर्ट खरीद प्रक्रिया में तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा को भी जांच के दायरे में लिया है। जांच अधिकारियों की टीम गुरुवार को बूढ़ानीलकण्ठ स्थित देउवा निवास के खंडहरनुमा परिसर में पहुंची और 'बयान के लिए उपस्थित हों' संबंधी नोटिस चस्पा किया। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यदि बयान के लिए बुलाया गया व्यक्ति संपर्क में नहीं आता, तो उसके स्थायी पते पर नोटिस तामील करना अनिवार्य होता है। बूढ़ानीलकण्ठ नगरपालिका–2 के वडाध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ ने बताया कि ब्यूरो की टीम को देउवा निवास परिसर में परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। इसके बाद ब्यूरो की टीम ने पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के निजी सचिव भानु देउवा को फोन कर नोटिस तामेल होने की जानकारी दी। नोटिस तामील प्रक्रिया में संबंधित नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ब्यूरो को संदेह है कि तत्कालीन विदेश मंत्री आरजू देउवा के हस्तक्षेप के कारण योग्यता पूरी न करने और अधिक राशि का प्रस्ताव देने वाली कंपनी को ठेका मिला। इसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। नोटिस चिपकाकर बयान के लिए बुलाने के बाद भी यदि वे उपस्थित नहीं होतीं, तो आगे क्या कदम उठाया जाए, इस पर ब्यूरो में चर्चा चल रही है। प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले इलाज के लिए सिंगापुर गए देउवा दंपत्ति अभी तक नेपाल नहीं लौटे हैं। उन्होंने दो दिन पहले ही सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग और विशेष अदालत को पत्र भेजकर जानकारी दी थी कि वे दो महीने बाद नेपाल लौटेंगे। ब्यूरो से जुड़े सूत्रों के अनुसार कागजी तौर पर कोई प्रत्यक्ष भूमिका न दिखने के बावजूद ठेका प्रक्रिया की डिजाइन तैयार करने, पैकेज बनाने और ठेकेदारों के बीच समन्वय कराने में केवल आरजू ही नहीं, बल्कि उनके बेटे जयवीर देउवा की संलिप्तता संबंधी शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। ब्यूरो के जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कुछ उपकरण बरामद किए गए हैं और फोन संपर्कों का विश्लेषण भी किया गया है। इन्हीं आधारों पर उनके खिलाफ भी जांच जरूरी मानी गई, इसलिए बयान के लिए बुलाने की कोशिश की गई। पासपोर्ट विभाग से ई-पासपोर्ट ठेका दिए जाने से पहले जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार सुनील थापा के बेटे सिद्धार्थ थापा समेत कुछ व्यक्तियों और पासपोर्ट विभाग के महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल के बीच कई बार मुलाकात हुई थी।

भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल

नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को मजबूत करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को देश के पहले स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल (एसीवी) को समुद्री बेड़े में शामिल किया गया। भारतीय तटरक्षक फ्लीट में एसीवी का शामिल होना देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिहाज से अहम है। कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि भारतीय तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारियों और शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह समारोह गोवा में हुआ। यह मौका स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने और जरूरी समुद्री प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कई स्टेकहोल्डर्स की लगातार कोशिशों के सफल नतीजे का प्रतीक है। इस एयर कुशन व्हीकल को भारत में ही डिजाइन और बनाया गया है, जो देश के समुद्री इंडस्ट्रियल बेस की बढ़ती ताकत को दिखाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने, घरेलू शिपबिल्डिंग विशेषज्ञता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को सहयोग करने की दिशा में जरूरी कदम है। यह जहाज समुद्री कार्यों में ऑपरेशनल मदद करेगा और समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करने की इसकी क्षमता को मजबूत करेगा। यह मौका भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय और भारत की इंडस्ट्री के बीच राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से एडवांस्ड स्वदेशी सॉल्यूशन देने में करीबी सहयोग को भी दिखाता है। ऐसी पहल देश की रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी उत्प्रेरक का काम करती हैं। एसीवी का शामिल होना स्वदेशी क्षमता विकास की दिशा में भारत की यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि है। यह आधुनिक, काबिल और भविष्य के लिए तैयार समुद्री सेना बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर किए गए प्रयासों को दिखाता है।

बंगाल : हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच में ममता बनर्जी की बहन के घर पहुंची सीआईडी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच में गुरुवार को सीआईडी की एक टीम कालीघाट स्थित पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहन के आवास पर पहुंची। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, जांच दल कथित फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की पड़ताल और आवश्यक जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से वहां पहुंचा था। हालांकि, सीआईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि, यह मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए प्रस्तुत एक प्रस्ताव (रिजॉल्यूशन) से जुड़ा है। आरोप है कि उस प्रस्ताव में कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों का उनकी जानकारी या सहमति के बिना उपयोग किया गया। शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। सीआईडी ने अब तक कई राजनीतिक नेताओं से पूछताछ की है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा विधायक कुणाल घोष, पूर्व मंत्री मदन मित्र सहित कई अन्य नेताओं को भी जांच एजेंसी ने तलब कर बयान दर्ज किए हैं। मामले से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है। सीआईडी सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई नेताओं के बयानों में परस्पर विरोधाभास सामने आए हैं। इसी कारण मामले की तह तक पहुंचने और वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच को और तेज किया गया है।

पंजाब में सीमा पार से हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार

एजेंसी, चंडीगढ़।

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हथियार तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके आठ तस्करों को 11 आधुनिक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि अमृतसर के गांव अटारी निवासी गुलाबजीत सिंह उर्फ प्रिंस (21) और हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत (23), गुरदासपुर के गांव हरदोवाल, कलानौर निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (24), अमृतसर के गांव रणियां निवासी कुलजीत सिंह (39) और शमशेर सिंह उर्फ शेरा (40), अमृतसर के गांव छेहरटा निवासी अमन राणा उर्फ चीनी (20), अमृतसर के गांव किरलगढ़ निवासी शरणजीत सिंह उर्फ सनी (29) और तरनतारन के गांव मालिया के रहने वाले अजय सिंह (23) को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बरामद हथियारों में चार .30 बोर (चीनी निर्मित), चार .30 बोर पीएक्स5 स्टॉर्म, एक .30 बोर जिगाना, एक 9 एमएम ग्लॉक (ऑस्ट्रियाई निर्मित) और एक 9 एमएम (ऑस्ट्रियाई निर्मित) तथा आठ जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस टीमों ने इनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक

जांच के अनुसार गिरफ्तार हथियार तस्कर कथित तौर पर अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल विदेशी कारिंदों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए ये हथियार आगे अपराधिक तत्वों को सप्लाई किए जाने थे, जिनका इस्तेमाल जबरन वसूली, हिंसक अपराधों और अन्य अवैध गतिविधियों में होना था। डीजीपी ने कहा कि नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और हथियारों का पता लगाने के लिए इस मामले में आगे-पीछे के संबंधों की जांच की जा रही है।

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्राप्त गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने गुलाबजीत उर्फ प्रिंस और हरप्रीत उर्फ प्रीत को दो पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान पुलिस टीमों ने गुरप्रीत उर्फ गोपी को चार पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया और उसके खुलासों के आधार पर पुलिस टीमों ने आगे उसके दो साथियों कुलजीत सिंह और शमशेर उर्फ शेरा को दो पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान गुरप्रीत उर्फ गोपी ने खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया एप्लिकेशनों के माध्यम से एक विदेशी गैंगस्टर के संपर्क में था, जो उनके लिए अटारी सेक्टर में विभिन्न स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से भेजी जाने वाली हथियारों की खेप का प्रबंध कर रहा था।

उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान पुलिस टीमों ने दो अन्य आरोपियों अमन राणा उर्फ चीनी और शरणजीत उर्फ सनी को दो पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया और उक्त आरोपियों के खुलासों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने एक पिस्तौल सहित अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जांच के अनुसार हरप्रीत उर्फ प्रीत, गुरप्रीत उर्फ गोपी, शरणजीत उर्फ सनी और अजय सिंह पहले हत्या, हत्या की कोशिश, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और चोरी के मामलों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश के आसार

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में 19-22 जून के दौरान तेज हवाओं तथा गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। दूसरी ओर देश के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में 19 जून को सुबह या दोपहर के समय 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40-42 डिग्री सेल्सियस और 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

बीस जून को भी यही स्थिति रहेगी। यहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36-38 डिग्री सेल्सियस और 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, 21 जून को दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36-38 डिग्री सेल्सियस और 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। बीस जून तक विदर्भ, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने की बहुत संभावना है। अगले 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

उत्तर-पश्चिम भारत के 18 से 22 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19-22 जून तक कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में 19-22 जून के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक जा सकती हैं।

केंद्र ने एससी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए जारी किए 6,208 करोड़ रुपये

एजेंसी, नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए इस वित्तीय वर्ष में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 6,208 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड राशि जारी की है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,208.08 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 47.53 लाख छात्रों को लाभ हुआ है। यह भी 2021-22 में डीबीटी अपनाए जाने के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस योजना में 1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 की अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या 16.63 लाख दर्ज की गई, जो

पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 61.92 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 562.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 26.79 लाख छात्रों को सीधा लाभ मिला है। 2022-23 में डीबीटी की शुरुआत के बाद से यह इस योजना के तहत अब तक की सबसे बड़ी राशि है। चालू वर्ष में (1 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक) लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 5.75 लाख हो गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (2.36 लाख) की तुलना में 143.64 प्रतिशत की वृद्धि है।

विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार की सहायता और लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि का मुख्य कारण डीबीटी व्यवस्था है। लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि के हस्तांतरण ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है, जिससे छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता मजबूत हुई है। यह विभाग सामाजिक न्याय की पहलों को मजबूत करने और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से वंचित समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाकिस्तान में सिख दंपति की गोली मारकर हत्या की भाजपा ने की कड़ी निंदा

एजेंसी, नई दिल्ली

पाकिस्तान सरकार की अल्पसंख्यकों और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा में विफलता की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी निंदा की है। मरदान के एक गुरुद्वारे में सिख दंपति की हत्या की निंदा करते हुए भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यह घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाती है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना राज्य प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हस्तक्षेप कर पाकिस्तान सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग की।

चुग ने गुरुवार को जारी बयान में इस हत्या को "बर्बर और बेहद चिंताजनक" बताते हुए कहा कि इस हमले से पाकिस्तान में रहने वाले सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसक घटनाएं सुरक्षा और न्याय प्रदान करने में पाकिस्तान की विफलता को उजागर करती हैं।

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा सरकार से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि हत्या के दोषियों

के साथ-साथ साजिश रचने वालों की भी पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दी जानी चाहिए। चुघ ने कहा कि कार्रवाई में किसी भी तरह की देरी सरकार की अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करेगी।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक गुरुद्वारे के भीतर वृद्ध सिख दंपति की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मर्दान जिले के बाबू मोहल्ला, ख्वाजा गंज बाजार स्थित गुरुद्वारे में अज्ञात हमलावरों ने 70 साल के जगन्नाथ और उनकी पत्नी आसमा वंती की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों गुरुद्वारे के सेवादार और देखरेख करने वाले थे।

ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा 1.44 करोड़ का गांजा जब्त, दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी, सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे करीब 209 किलोग्राम गांजा को जब्त किया है। इस मामले में एक युवक और एक नाबालिग को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान गांजा, ट्रेलर, फ्लोर्सपार पाउडर और मोबाइल फोन समेत कुल एक करोड़ 66 लाख 20 हजार 460 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली के नेतृत्व में पुलिस टीम को 17 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा भरकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा है।

इस सूचना पर पुलिस ने रणनीति बनाते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन कर ग्राम बोडासागर स्थित सागर फेमिली ढाबा के सामने खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध टाटा सिगना ट्रेलर क्रमांक आरजे 09 जीसी 5216 को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

लाशी के दौरान ट्रेलर में रखी 8 प्लास्टिक

बोरियों से कुल 40 पैकेट गांजा बरामद किया गया। प्रत्येक पैकेट का वजन लगभग 5 किलोग्राम था। जब्त गांजा का कुल वजन 208.965 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत एक करोड़ 44 लाख 48 हजार 250 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेलर को भी जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा ट्रेलर में भरा फ्लोर्सपार पाउडर, जिसकी कीमत 21 लाख 42 हजार 210 रुपये है। आरोपितों के कब्जे से मिले वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री का कुल मूल्य एक करोड़ 66 लाख 20 हजार 460 रुपये आंका गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी डभरा सुमीत गुप्ता के मार्गदर्शन में चौकी फगुरम और थाना डभरा पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की।

पूछताछ के दौरान आरोपितों द्वारा गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जिले के थाना जेवाजा क्षेत्र निवासी अर्पित सिंह (20 वर्ष), पिता रमेश सिंह तथा उसके साथ मौजूद एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 219/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपितों को पकड़ने के लिए जिले में लगातार 26 घंटे तक बैरिकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सीपी कंवर, सहायक उप निरीक्षक हीराराम संवरा, प्रधान आरक्षक टीकम सिंह साव, अश्वनी सिदार, लक्ष्मीनारायण राठौर सहित साइबर सेल और पुलिस बल के अन्य जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सरकार का दावा- देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर

एजेंसी, नई दिल्ली

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि देशभर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। सरकार की रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटरशिप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, जबकि पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग के मुकाबले 1.47 करोड़ डिलीवरी की गई हैं।

पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में बताया कि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) बुकिंग का बैकलॉग घटकर अब 3.1 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि 22,945 टन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और 1.98 लाख पांच किलो वाले सिलेंडर बेचे गए हैं। उन्होंने बताया कि मार्च से अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शन में गैस सप्लाई शुरू की गई है, जबकि 3.22 लाख और कनेक्शन के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। कुल 9.94 लाख नए ग्राहकों ने पीएनजी सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। शर्मा ने कहा कि ई85 के लिए लगभग 48 रिटेल आउटलेट हैं, जहां ई85 को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक 500 और रिटेल आउटलेट में यह सुविधा होगी और अगले साल के आखिर तक 5000 और यानी यह संख्या 5000 तक पहुंच जाएगी।

पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी ले जाने वाला एक जहाज शुक्रवार को सुबह गुजरात के दहेज में लंगर डालेगा।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव का मतदान संपन्न, मतगणना शुरू

एजेंसी, बेंगलुरु

कर्नाटक राज्य की विधान परिषद के लिए सात सीटों के लिए चुनाव में आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। मतदान के बाद मतों की गणना शुरू हो गई है।

दरअसल, राज्य की विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इन सीटों के लिए विधानसौधा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, विपक्ष के नेता आर. अशोक तथा जनता दल (सेक्युलर) विधायक दल के नेता सीबी सुरेश बाबू सहित कई प्रमुख नेताओं ने

मतदान में हिस्सा लिया। मतदान के दौरान नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टियों की जीत को लेकर विश्वास व्यक्त किया।

राज्य की सात विधान परिषद की सात सीटों के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पांच उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दो उम्मीदवारों को अवसर दिया है। जनता दल (सेक्युलर) ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा है, जिससे अंतिम सीट के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर तीन दिवसीय महाअभियान, 21 जून को प्रधानमंत्री करेंगे मुख्य कार्यक्रम में शिरकत : सीएम

एजेंसी, कोलकाता

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल में आगामी 19 से 21 जून तक तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को नवान्न में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान मैदान क्षेत्र में कीचड़ की आशंका को देखते हुए योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रेड रोड पर किया जाएगा। 21 जून को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस के आयोजन के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अब तक 38 हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है और कई लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के अनुसार, 19 जून सुबह सात

बजे 'रन फॉर योगा' का आयोजन किया जाएगा। यह मैराथन कोलकाता नगर निगम मुख्यालय से राइटर्स बिल्डिंग तक निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दूसरे दिन, 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन शाम साढ़े पांच बजे के बाद गंगा नदी पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें ड्रोन के माध्यम से योग से संबंधित आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन होगा। प्रतिभागियों को सुबह 6:15 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा, जिसके बाद आयुष मंत्रालय के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योग सत्र शुरू होगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि योग के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार आधिकारिक रूप से इस आयोजन में व्यापक भागीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि योग दिवस आज पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण और समयानुकूल पहल के रूप में स्वीकार किया जा चुका है तथा 175 से अधिक देश इसकी महत्ता को मान्यता दे चुके हैं। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जब योग दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो वह केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाता है।

अमेरिका-ईरान 14 सूत्रीय इस्लामाबाद एमओयू: पश्चिम एशिया में शांति का नया अध्याय या 60 दिनों का अस्थायी विराम? -पूरे विश्व की निगाहें इन सीमित दिनों की वार्ता पर? -समग्र व्यापक विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 18 जून 2026 को वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिला,जब अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरानी राष्ट्रपति ने बहुचर्चित 14-सूत्रीय इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर गुरुवार सुबह डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 18 जून 2026 को इस समझौते पर आधिकारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह तुरंत प्रभावी हो गया दोनों देशों के बीच इस अंतरिम समझौते के मुख्य मसौदे पर सहमति रविवार,14 जून 2026 को ही बन गई थी. इसके बाद 17 जून 2026 को अमेरिकी अधिकारियों ने इसके 14 बिंदुओं को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने पढ़ा था, 18 जून 2026 से यह समझौता लागू होते ही दोनों पक्षों के बीच अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और स्थायी शांति समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत की औपचारिक शुरुआत हो गई है,इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे सैन्य तनाव, होर्मुज

» **वास्तविक परीक्षा अभी शुरू हुई है, वार्ता सफल रही तो पश्चिम एशिया में एक नया भू- राजनीतिक युग प्रारंभ हो सकता है, विफलता की स्थिति में तनाव पुनःउभरेगा**

» **अमेरिका-ईरान समझौता केवल द्विपक्षीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जासुरक्षा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तेल बाजार, शेयर बाजारों, समुद्री परिवहन, पश्चिम एशिया की सामरिक स्थिरता तथा विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने पड़ेगा -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र**

जलडमरूमध्य संकट, आर्थिक प्रतिबंधों और परमाणु विवाद को नियंत्रित करने के लिए एक अंतरिम ढांचा औपचारिक रूप से लागू हो गया। यह समझौता तत्काल प्रभाव से युद्धविराम लागू करता है तथा अगले 60 दिनों के भीतर एक स्थायी शांतिसमझौते की दिशा में वार्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह समझौता केवल दो देशों के बीच का द्विपक्षीय दस्तावेज नहीं है,बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जासुरक्षा अंतरराष्ट्रीय व्यापार,तेल बाजार, शेयर बाजारों, समुद्री परिवहन,पश्चिम एशिया की सामरिक स्थिरता तथा विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। यही कारण है कि न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो, लंदन से लेकर मुंबई और बीजिंग से लेकर ब्रुसेल्स तक वित्तीय संस्थान, निवेशक, तेल कंपनियां और रणनीतिक विशेषज्ञ इस समझौते पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। साथियों, समझौते का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तत्काल और व्यापक युद्धविराम है।अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को समाप्त करने तथा भविष्य में एक-दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग न करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पिछले कई महीनों से क्षेत्र में जिस प्रकार मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, नौसैनिक अवरोध और प्रॉक्सी संघर्ष चल रहे थे, उनके कारण पूरा पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया था। ऐसे समय में युद्धविराम की यह घोषणा वैश्विक राहत का विषय बनी है।इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण आधार दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है। पिछले चार दशकों से अमेरिका और ईरान के संबंध अविश्वास, प्रतिबंधों,सैन्य धमकियों और वैचारिक संघर्षों से प्रभावित रहे हैं। ऐसे में यह प्रावधान भविष्य के संबंधों के लिए एक नया कूटनीतिक आधार तैयार कर सकता है। तीसरा और सबसे चर्चित बिंदु 60 दिनों की वार्ता अवधि है। वास्तव में यह समझौता अंतिम शांति संधि नहीं है बल्कि एक अंतरिम व्यवस्था है। अगले 60 दिनों में दोनों पक्ष परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों की समाप्ति, सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग जैसे जटिल मुद्दों पर अंतिम समझौते का प्रयास करेंगे।इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि वास्तविक परीक्षा अभी शुरू हुई है। यदि वार्ता सफल रही तो पश्चिम एशिया में एक नया भू-राजनीतिक युग प्रारंभ

हो सकता है, जबकि विफलता की स्थिति में तनाव पुनः उभर सकता है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसेमहत्वपूर्ण बिंदु होर्मुज जलडमरूमध्य का पुनः खुलना है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। हाल के तनावों के कारण यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार- चढ़ाव आया। समझौते के अनुसार ईरान अगले 60 दिनों तक वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और शुल्क-मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा, जबकि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आने की संभावना बढ़ गई है। साथियों, भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह प्रावधान विशेष महत्व रखता है। भारत अपने ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है। यदि होर्मुज मार्ग सुचारू रूप से खुला रहता है तो तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, आयात लागत नियंत्रित रहेगी और मुद्रास्फीति को सीमित रखने में सहायता मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।समझौते का छठा बिंदु 300 अरब डॉलर केपुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास फंड से जुड़ा है।अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह प्रत्यक्ष युद्ध हर्जाना नहीं होगा, बल्कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा समर्थित निवेश एवं विकास ढांचा होगा। हालांकि इस प्रावधान को लेकर अभी भी कई प्रश्न बने हुए हैं, क्योंकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह राशि अमेरिकी करदाताओं के धन से सीधे नहीं दी जाएगी बल्कि इसमें क्षेत्रीय निवेश, निजी पूंजी और ईरान की उपलब्ध संपत्तियों का उपयोग शामिल हो सकता है। ईरान के लिए यह आर्थिक जीवनरेखा साबित हो सकती है। वर्षों से चले आ रहे प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था, मुद्रा, निवेश वातावरण और ऊर्जा क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यदि निवेश प्रवाह शुरू होता है तो ईरान के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन नेटवर्क और औद्योगिक विकास को नया प्रोत्साहन सटीकता से मिल सकता है। साथियों, सातवां और आठवां बिंदु परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। ईरान ने पुनः घोषणा की है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा तथा अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के प्रबंधन और संवर्धन स्तर कम करने पर बातचीत करेगा। इस प्रक्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की केंद्रीय भूमिका होगी। आईएईए प्रमुख ने भी इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि अब तकनीकी स्तर पर कार्य शुरू होगा और निरीक्षण तथा सत्यापन प्रणाली विकसित की जाएगी।यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमाणु मुद्दा ही अमेरिका-ईरान विवाद का मूल कारण रहा है। यदि दोनों पक्ष इस विषय पर स्थायी समाधान तक पहुंच जाते हैं तो यह केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी।समझौते में यह भीप्रावधान है कि अमेरिका ईरानी तेल निर्यात के लिए तत्काल छूट प्रदान करेगा और प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील देगा। इसके अतिरिक्त ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ईरानी तेल की वापसी संभव होगी, जो वैश्विक आपूर्ति बढ़ाकर तेल कीमतों को स्थिर रखने में सटिका से योगदान दे सकती है। साथियों, हालांकि इस समझौते के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती विश्वास की है। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों का अविश्वास कुछ हस्ताक्षरों से समाप्त नहीं हो सकता।दूसरी चुनौती क्षेत्रीय राजनीति की है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और इजराइल से जुड़े मुद्दे अब भी संवेदनशील बने हुए हैं।यदि किसी भी मोर्चे पर तनाव बढ़ता है तो समझौते की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।तीसरी चुनौती घरेलू राजनीति की है।अमेरिका और ईरान दोनों देशों में ऐसे राजनीतिक समूह मौजूद हैं जो इस समझौते को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। अमेरिका में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वाशिंगटन ने बहुत अधिक रियायतें दे दी हैं, जबकि ईरान में भी कुछ वर्ग इसे पर्याप्त नहीं मानते।चौथी चुनौती निगरानी और अनुपालन की है। समझौते में एक विशेष कार्यकारी निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है जो दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं की निगरानी करेगा। लेकिन वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों देश अपने वादों को समय पर और पारदर्शी ढंग से लागू करते हैं। साथियों, विश्व शेयर बाजारों ने इस समझौते को फिलहाल सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है। निवेशकों को उम्मीद है कि ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता, समुद्री व्यापार की बहाली और क्षेत्रीय तनाव में कमी से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता घटेगी। हालांकि अधिकांश वित्तीय संस्थान अभी भी अगले 60 दिनों को निर्णायक अवधि मान रहे हैं। यदि वार्ता सफल रहती है तो वैश्विक निवेश वातावरण को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कहा जा सकता है कि 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' युद्ध का अंतिम समाधान नहीं बल्कि शांति की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता पश्चिम एशिया में स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक पुनरुद्धार की आशा जगाता है, लेकिन इसकी सफलता पूर्णतः अगले 60 दिनों के घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान अपने ऐतिहासिक अविश्वास को पीछे छोड़कर स्थायी शांति की ओर बढ़ते हैं, या फिर यह समझौता भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अनेक अधूरे प्रयोगों की सूची में शामिल हो जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 17 जून 2026 का यह समझौता 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं में से एक बन चुका है।

संकलनकर्ता लेखक - क्र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती : एक संत की हत्या पर न्याय का इंतजार

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के सामने कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हैं, जिनका उत्तर सिर्फ शासन की नीयत और प्रशासनिक जवाबदेही में छिपा हुआ है। ओडिशा के प्रसिद्ध संत, जनजातीय समाज के हितैषी और सनातन संस्कृति के प्रखर प्रवक्ता श्रद्धेय स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या ऐसा ही एक प्रश्न बनकर आज भी देश के सामने खड़ी है। उनकी हत्या को लगभग दो दशक बीतने को हैं, किंतु न्याय की प्रक्रिया आज भी अधूरी दिखाई देती है। अब जब उनकी हत्या और उसके बाद हुई हिंसा की जांच से संबंधित महत्वपूर्ण आयोगों की रिपोर्टों के ही लापता होने की बात सामने आई है, तब यह मामला पूरे प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता का विषय बन गया है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत में किसी न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी गायब हो सकती है? यदि हां, तो फिर देश की संस्थाओं पर जनता भरोसा कैसे करे? जिन रिपोर्टों को वर्षों की जांच, साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर तैयार किया गया, वे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद अचानक गायब हो जाती हैं और किसी को उनकी जानकारी नहीं होती। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा हुआ है? स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती स्मृति न्यास ने जो सवाल उठाए हैं, वे उनके अनुयायियों की भावनाओं से जुड़े होने के साथ आज हर उस नागरिक की चिंता हैं जो कानून के शासन में विश्वास रखता है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति की फाइल गायब हो जाए तो उसे अपनी गलती का दंड भुगतना पड़ता है लेकिन जब राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों से न्यायिक जांच रिपोर्टें लापता हो जाती हैं, तब सवाल यह है कि आखिर जवाबदेही तय करने में वर्षों क्यों लग रहे हैं? यह भी विचारणीय है कि जिन रिपोर्टों को 2016 और 2018 में मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया था, वे 2024 तक सुरक्षित क्यों नहीं रखी जा सकीं? उसी अवधि की अन्य फाइलें वापस मिल जाती हैं, किंतु सबसे संवेदनशील जांच रिपोर्टें गायब रहती हैं। क्या यह मात्र संयोग है? क्या सरकार जनता को यह विश्वास दिला सकती है कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं ही लुप्त हो गए? क्या इससे यह संदेह पैदा नहीं होता कि भले ही सरकार उड़ीसा में बदल गई है, किंतु कथित अपराधियों की पकड़ सचिवालय पर अब भी भारी है! निश्चित ही इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यह सर्वविदित है कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं पर संस्थाएं और अभिलेख जनता की संपत्ति होते हैं। यदि सत्ता परिवर्तन के दौर में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गायब होने की आशंका पैदा होती है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि रिपोर्टें कहां हैं, उन्हें किसने संभाला और आखिर उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। एक और बड़ा प्रश्न न्याय प्रक्रिया को लेकर है। यदि हत्या के इतने वर्षों बाद भी आयोगों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकीं, तो आखिर किसकी रक्षा की जा रही है? जनता को सत्य जानने का अधिकार है। लोकतंत्र में गोपनीयता का उपयोग सत्य को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि रिपोर्टों में ऐसे तथ्य हैं जो समाज को वास्तविकता से अवगत करा सकते हैं, तो उन्हें सार्वजनिक करने में संकोच क्यों? वस्तुतः यह सभी को स्मरण रखना चाहिए कि संत स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए लंबा कार्य करनेवाले महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मुखर आवाज उठाई थी। ऐसे व्यक्ति की हत्या यदि आज भी विवादों और अनुत्तरित प्रश्नों से घिरी हुई है तो यह किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं बल्कि उन हजारों-लाखों लोगों की भावनाओं के साथ भी अन्याय है जो उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अतः सरकार का यह दायित्व है कि वह सिर्फ प्राथमिकी दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री न माने। इससे अधिक आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध हो। यदि दस्तावेजों को जानबूझकर हटाया गया, छिपाया गया या नष्ट किया गया है तो यह न्याय प्रक्रिया को बाधित करने का गंभीर कृत्य है। ऐसे लोगों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों द्वारा सीबीआई जांच की मांग भी इसी अविश्वास की पृष्ठभूमि में उठी है। जब राज्य की व्यवस्था स्वयं संदेह के घेरे में हो तब स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्र एजेंसी की मांग उठेगी। सरकार को इस मांग को जनता के विश्वास की कसौटी पर देखना चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी को इस पूरे मामले में जांच अतिशीघ्र सौंप देना चाहिए। 2026 स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का जन्म शताब्दी वर्ष है। देशभर में उनके योगदान को स्मरण करने की तैयारी हो रही है, किंतु विडंबना देखिए; जिस संत को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही है, उनकी हत्या के पीछे का पूरा सच आज भी धुंध में छिपा हुआ है। क्या यह किसी सभ्य लोकतंत्र के लिए गौरव का विषय हो सकता है? ऐसे में आज आवश्यकता व्यवस्था में जनता का विश्वास पुनर्स्थापित करने की है। अतः मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की सरकार के सामने यह अवसर भी है और चुनौती भी। यदि वह इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता दिखाती है, रिपोर्टों को सार्वजनिक करती है, दोषियों की जवाबदेही तय करती है और हत्या की साजिश से जुड़े हर व्यक्ति को कानून के कटघरे तक पहुंचाती है, तभी यह कहा जा सकेगा कि न्याय जीवित है। अन्यथा देश यह पूछने को मजबूर होगा कि आखिर एक संत की हत्या पर न्याय का इंतजार कब तक? क्या न्याय भी किसी फाइल की तरह सरकारी दफ्तरों में खो गया है? और यदि ऐसा नहीं है तो सत्य को सामने आने से रोका क्यों जा रहा है? अब इन प्रश्नों का उत्तर ओडिशा सरकार के पूरे लोकतांत्रिक तंत्र को देना ही चाहिए ।

राम का नाम बदनाम ना करो राम मंदिर,आस्था,प्रबंधन और जवाबदेही के बीच उठते सवाल - राम-राम जपना,चढ़ावे का मालअपना ?

आलेख–विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला',स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार

भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं,भाषाई विविधता या सांस्कृतिक विरासत से नहीं होती,बल्कि उसकी गहरी धार्मिक चेतना और आस्था से भी होती है।यहाँ मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थल नहीं हैं,बल्कि समाज की भावनाओं,विश्वासों और सांस्कृतिक निरंतरता के केंद्र भी हैं। करोड़ों लोग अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मंदिरों में दान,दक्षिणा,चढ़ावा और सेवा अर्पित करते हैं।यह दान केवल आर्थिक लेन-देन नहीं होता,बल्कि भक्त और भगवान के बीच विश्वास का एक आध्यात्मिक सेतु होता है। यही कारण है कि जब किसी धार्मिक संस्था,ट्रस्ट या मंदिर के प्रबंधन को लेकर प्रश्न उठते हैं, तब मामला केवल प्रशासनिक या आर्थिक नहीं रह जाता,बल्कि सीधे-सीधे आस्था,विश्वास और जवाबदेही से जुड़ जाता है।

ऐसे समय में लोकजीवन में प्रचलित एक पुरानी कहावत अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाती है- "राम-राम जपना,चढ़ावे का माल अपना।" यह कहावत किसी धर्म, देवता या आस्था का उपहास नहीं करती,बल्कि उन प्रवृत्तियों पर व्यंग्य करती है जो धर्म और नैतिकता की बात तो करती हैं, किंतु व्यवहार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से दूर दिखाई देती हैं। आज जब अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है,तब यह कहावत कुछ असहज किंतु आवश्यक प्रश्न भी खड़े करती है।अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं था।यह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था।दशकों तक चले संघर्ष,सामाजिक विमर्श, राजनीतिक बहसों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद जब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तब देश के कोने-कोने से लोगों ने इसे अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय मानकर सहयोग दिया। गाँवों से लेकर महानगरों तक,भारत से लेकर विदेशों तक,करोड़ों लोगों ने आर्थिक और भावनात्मक रूप से इस अभियान में भागीदारी की।

किसी ने एक रुपया दिया,किसी ने लाखों रुपये का दान किया।अनेक श्रद्धालुओं ने सोना,चाँदी,हीरे,मोती और बहुमूल्य रत्न अर्पित किए। कई परिवारों ने पीढ़ियों से संभालकर रखे गए आभूषण रामलला को समर्पित कर दिए। महिलाओं ने अपने विवाह के गहने तक दान कर दिए।बुजुर्गों ने अपनी जीवनभर की बचत का हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित किया। यह केवल आर्थिक योगदान नहीं था,बल्कि श्रद्धा,समर्पण और विश्वास की अभिव्यक्ति थी।

राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिखाई दी। गरीब,मध्यमवर्गीय और संपन्न - सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। यही कारण है कि मंदिर से जुड़ा प्रत्येक संसाधन केवल संपत्ति नहीं,बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक माना जाता है।लोगों ने यह मानकर दान दिया कि उनका योगदान भगवान राम के भव्य मंदिर और उससे जुड़े धार्मिक-सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगेगा।भारतीय संस्कृति में दान और चढ़ावे की परंपरा अत्यंत प्राचीन है।मंदिरों को सदियों से समाज ने केवल पूजा स्थलों के रूप में नहीं,बल्कि लोककल्याण के केंद्र के रूप में भी देखा है।इतिहास गवाह है कि अनेक मंदिरों ने शिक्षा,चिकित्सा,सामाजिक सहायता और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रद्धालु जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं,तब वे केवल धन नहीं देते, बल्कि संस्था के प्रति अपना विश्वास भी सौंपते हैं।यही विश्वास किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूँजी होता है।यही कारण है कि जब चढ़ावे में प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं, आभूषणों और रत्नों के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता,चोरी अथवा अभिलेखीय विसंगतियों की चर्चा सामने आती है,तो समाज में स्वाभाविक रूप से चिंता उत्पन्न होती है।पिछले कुछ समय से विभिन्न माध्यमों में ऐसी खबरें और आरोप चर्चा का विषय बने कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई कुछ बहुमूल्य वस्तुओं के संबंध में प्रश्न उठे हैं।कुछ शिकायतों में यह आशंका व्यक्त की गई कि चढ़ावे में प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति को लेकर पारदर्शिता अपेक्षित स्तर की नहीं है।इन चर्चाओं ने मामले को सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया और जाँच एजेंसियों की संभावित भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठने लगे।यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी आरोप को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप,जाँच और न्यायिक निष्कर्ष तीन अलग-अलग चरण होते हैं।केवल आरोपों के आधार पर किसी संस्था या व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो, तब उठ रहे प्रश्नों को केवल अफवाह कहकर खारिज कर देना भी उचित नहीं माना जा सकता।जनविश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों अनिवार्य हैं।राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत स्मृति का प्रतीक है। इसीलिए उससे जुड़े प्रत्येक निर्णय,प्रत्येक व्यवस्था और प्रत्येक संसाधन पर समाज की निगाह रहती है। श्रद्धालु यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा समर्पित धन और बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है,उनका लेखा-जोखा कैसे रखा जा रहा है,क्या स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था है,क्या समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाती है तथा क्या चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित और सत्यापित रूप में उपलब्ध है।ये प्रश्न किसी धर्म, व्यक्ति या संस्था विशेष के विरोध में नहीं हैं।वास्तव में ये प्रश्न उन करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा से जुड़े हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को अपना व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दायित्व मानकर सहयोग दिया था।लोकतांत्रिक समाज में पारदर्शिता को अविश्वास का प्रतीक नहीं,बल्कि विश्वास को और अधिक मजबूत करने का माध्यम माना जाता है।यहीं पर राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन से जुड़ी प्रबंधन व्यवस्था तथा प्रबंधन समिति की भूमिका चर्चा के केंद्र में आ जाती है।किसी भी बड़े धार्मिक संस्थान की विश्वसनीयता केवल उसकी भव्यता से निर्धारित नहीं होती।उसके प्रशासनिक मानक,वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।यदि प्रबंधन व्यवस्था पारदर्शी,व्यवस्थित और उत्तरदायी दिखाई देती है, तो श्रद्धालुओं का विश्वास स्वतः बढ़ता है।यदि कहीं अस्पष्टता या सूचना का अभाव दिखाई देता है,तो प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है।

जब किसी संस्था को जनता का व्यापक समर्थन और संसाधन प्राप्त होते हैं,तब उसके साथ जवाबदेही भी जुड़ जाती है।श्रद्धालु यह अपेक्षा करते हैं कि मंदिर से जुड़े सभी आर्थिक और प्रशासनिक कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हों।यदि कहीं कोई शिकायत या संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किया जाए। यही किसी भी प्रतिष्ठित संस्था की साख को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है।भारत का संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं है।चाहे वह धार्मिक संस्था हो,सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो अथवा कोई बड़ी कॉरपोरेट इकाई—सभी के लिए कानून समान है। इसलिए यदि किसी प्रकार की शिकायत सामने आती है,तो जाँच एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।हालाँकि जाँच एजेंसियों की भूमिका को लेकर भी संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।किसी संस्था के विरुद्ध जाँच होना अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होता।जाँच का उद्देश्य दोषी ठहराना नहीं,बल्कि सत्य तक पहुँचना होता है।यदि सब कुछ व्यवस्थित और पारदर्शी है, तो जाँच संस्था की विश्वसनीयता को और मजबूत कर सकती है। यदि कहीं कोई त्रुटि या अनियमितता है, तो उसका सामने आना भी आवश्यक है।यही कानून के शासन का मूल आधार है।दुर्भाग्य से समाज में अक्सर दो चरम स्थितियाँ देखने को मिलती हैं।एक वर्ग बिना किसी निष्कर्ष के ही आरोपों को सत्य मान लेता है। दूसरा वर्ग केवल भावनाओं के आधार पर हर प्रश्न को साजिश घोषित कर देता है।दोनों ही दृष्टिकोण स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श के लिए उचित नहीं हैं।सत्य तक पहुँचने का मार्ग तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्ष जाँच से होकर गुजरता है।

भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति में मर्यादा,न्याय और सत्य के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। रामराज्य की अवधारणा केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि सुशासन का आदर्श भी है। रामराज्य का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जहाँ शासन पारदर्शी हो,न्याय निष्पक्ष हो और जनता का विश्वास सर्वोपरि हो। वहाँ राजा स्वयं भी नैतिक जवाबदेही से मुक्त नहीं था। यही कारण है कि भगवान राम आज भी केवल धार्मिक श्रद्धा के विषय नहीं,बल्कि आदर्श शासन और नैतिक नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं।यदि राम के नाम पर निर्मित किसी संस्था या व्यवस्था में पारदर्शिता की माँग उठती है,तो उसे विरोध के रूप में नहीं,बल्कि रामराज्य के आदर्शों के अनुरूप सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन स्वयं सत्य, मर्यादा और उत्तरदायित्व का संदेश देता है।इतिहास गवाह है कि धर्म का उद्देश्य सदैव समाज को नैतिक दिशा देना रहा है।मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा, सेवा, समाज-सुधार तथा जनकल्याण के अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।भारतीय समाज में धार्मिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का एक बड़ा कारण उनकी सेवा-परंपरा भी रही है।इस कारण जब किसी प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था पर कोई प्रश्न उठता है, तो उसका प्रभाव केवल उस संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक सामाजिक विश्वास को भी प्रभावित करता है।समय-समय पर कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में अपने निजी हितों को साधने का प्रयास भी किया है। ऐसे लोगों के कारण न केवल संस्थाओं की छवि प्रभावित होती है,बल्कि वास्तविक धार्मिक मूल्यों को भी क्षति पहुँचती है। यही कारण है कि समाज में यह कहावत जन्मी— "राम-राम जपना, चढ़ावे का माल अपना।"यह कहावत आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह मानव स्वभाव की उस कमजोरी की ओर संकेत करती है, जिसमें व्यक्ति धार्मिकता का प्रदर्शन तो करता है, किंतु उसके आचरण में ईमानदारी और जवाबदेही का अभाव होता है। यदि किसी धार्मिक संस्था में चढ़ावे या दान से संबंधित कोई अनियमितता होती है,तो वह केवल आर्थिक अपराध नहीं रह जाता। वह श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ भी विश्वासघात बन जाता है।

विश्वास किसी भी धार्मिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पूँजी होता है। सोना-चाँदी और बहुमूल्य रत्नों की कीमत बाजार तय करता है,किंतु श्रद्धालुओं की भावनाओं की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए यदि कभी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो,तो उसका समाधान शीघ्र,निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से होना चाहिए।

आज तकनीक ने पारदर्शिता के अनेक साधन उपलब्ध करा दिए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड,ऑनलाइन ऑडिट,वीडियो निगरानी,संपत्ति का सार्वजनिक अभिलेखीकरण, स्वतंत्र लेखा परीक्षण और समय-समय पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग जैसी व्यवस्थाएँ किसी भी धार्मिक संस्था की विश्वसनीयता को मजबूत कर सकती हैं।राम मंदिर जैसे विश्वस्तरीय धार्मिक केंद्र में ऐसी व्यवस्थाएँ केवल प्रशासनिक औपचारिकताएँ नहीं,बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास की सुरक्षा का माध्यम हैं।समय की माँग है कि धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बोझ नहीं,बल्कि प्रतिष्ठा का आधार माना जाए। जितनी बड़ी संस्था होगी, उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी होगी। यह सिद्धांत लोकतंत्र, प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं - सभी पर समान रूप से लागू होता है।

आवश्यकता इस बात की है कि आस्था और जवाबदेही को एक-दूसरे का विरोधी नहीं,बल्कि सहयोगी माना जाए।जहाँ पारदर्शिता होगी, वहाँ संदेह कम होंगे। जहाँ जवाबदेही होगी, वहाँ विश्वास मजबूत होगा।जहाँ विश्वास मजबूत होगा,वहाँ आस्था की गरिमा स्वतः सुरक्षित रहेगी।

अंततः "राम-राम जपना, चढ़ावे का माल अपना" केवल एक व्यंग्यात्मक कहावत नहीं, बल्कि समाज को सचेत करने वाला दर्पण है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म का वास्तविक आधार ईमानदारी, सत्य,सेवा और नैतिकता है।राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़ी हर व्यवस्था को संदेह से ऊपर, पारदर्शी और उत्तरदायी होना चाहिए।

यदि कहीं कोई शिकायत है,तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यदि कोई आरोप है, तो उसका तथ्यात्मक परीक्षण होना चाहिए। यदि सब कुछ सही है, तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।इससे न केवल विवादों का समाधान होगा,बल्कि श्रद्धालुओं का विश्वास भी और अधिक मजबूत होगा।

भगवान राम केवल श्रद्धा के नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और मर्यादा के भी प्रतीक हैं।राम के मंदिर की वास्तविक शक्ति उसकी भव्यता, ऊँचे शिखरों या बहुमूल्य चढ़ावों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो करोड़ों लोगों ने उसमें समर्पित किया है।उस विश्वास की रक्षा करना ही आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।यही रामभक्ति की कसौटी है,यही सुशासन की पहचान है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आस्था,पारदर्शिता और जवाबदेही तीनों साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

धोनी से आगे निकले रोहित

● सचिन, युवराज, सहवाग इस नंबर पर; लिस्ट-ए में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारत के पूर्व कप्तान व ओपनर बैटर रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 39 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली और लिस्ट ए क्रिकेट में अपने 14 हजार रन पूरे किए। यही नहीं लिस्ट ए क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में एमएस धोनी से आगे हैं।

रोहित शर्मा के लिस्ट ए क्रिकेट में अब 345 पारियों में 14,038 रन हो गए हैं और वो एमएस से इस लिस्ट में आगे हैं जिनके लिस्ट ए क्रिकेट में 365 पारियों में 13,353 रन थे। लिस्ट ए क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है जिन्होंने 538 पारियों में 21,999 रन बनाए थे जबकि विराट कोहली 334 पारियों में 16,447 रन बना चुके हैं और वो दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर्स में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 421 पारियों में 15,622 रन बनाए थे जबकि राहुल द्रविड़ ने 416 पारियों में 15,271 रन बनाए थे और वो सूची में चौथे नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा पांचवें तो धोनी छठे स्थान पर हैं। युवराज सिंह इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं जिन्होंने लिस्ट ए में खेले 389 मैचों में कुल 12,663 रन बनाए थे जबकि वीरेंद्र सहवाग 10वें नंबर पर हैं जिन्होंने 321 पारियों में कुल 10,454 रन बनाए थे। शिखर धवन 9वें तो गौतम गंभीर 11वें स्थान पर हैं।

लिस्ट ए में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 भारतीय

21999 रन - सचिन तेंदुलकर (538)
16447 रन - विराट कोहली (334)
15622 रन - सौरव गांगुली (421)
15271 रन - राहुल द्रविड़ (416)
14038 रन - रोहित शर्मा (345)
13353 रन - महेंद्र सिंह धोनी (365)
12941 रन - मोहम्मद अजहरुद्दीन (399)
12663 रन - युवराज सिंह (389)
12074 रन - शिखर धवन (298)
10454 रन - वीरेंद्र सहवाग (321)
10077 रन - गौतम गंभीर (292)

कांगो की मजबूत डिफेंस के आगे

बेबस दिखे रोनाल्डो

पुर्तगाल को नहीं मिल पाई जीत

नई दिल्ली (एजेंसी)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-K के मुकाबले में पुर्तगाल को कांगो के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा और ये टीम जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत नहीं कर पाई। एक तरफ जहां मेसी ने अपने पहले मुकाबले में 3 गोल दागे तो वहीं दुनिया के दिग्गज फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कांगो के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद पाए और अपनी टीम के लिए एक भी गोल नहीं कर पाए। कांगो और पुर्तगाल के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा।

रोमांचक रहा कांगो बनाम पुर्तगाल मुकाबला- कांगो और पुर्तगाल के बीच का मैच ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला गया था जिसमें पुर्तगाल ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाया और छठे मिनट में ही इस टीम के लिए पहला गोल जोआओ नेवेस ने दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। नेवेस ने पेड्रो नेटो के शानदार क्रॉस पर बेहतरीन हेडर लगाते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाने का काम किया। 0-1 से पिछड़ने के बाद कांगो ने पूरा जोर लगाया, लेकिन पहले हाफ के आखिरी समय तक ये टीम कोई गोल नहीं कर पाई, लेकिन पहले हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में आर्थर मासुआकू के सटीक क्रॉस पर योआने विस्सा ने दमदार हेडर लगाकर इतिहास रच दिया और गोल करते हुए टीम को 1-1 की बराबरी पर ला दिया।

घाना ने पनामा को 1-0 से हराया

कालेब यिरेंकी बने जीत के नायक

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत घाना ने जीत के साथ की है। ग्रुप एल के मुकाबले में घाना ने कालेब यिरेंकी के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की बदौलत पनामा को 1-0 से मात दी। मैच की शुरुआत में पनामा ने अच्छा खेल दिखाया। आमिर मुरिलो के लो क्रॉस पर सेसिलियो वाटरमैन को गोल का मौका मिला, लेकिन घाना के गोलकीपर बेंजामिन असारे ने डाइव लगाते हुए शानदार बचाव किया। इसके बाद पनामा को एक और मौका मिला, जब असारे का खराब पंच सीधे जियोवानी रामोस के पास गिरा, लेकिन वह भी इसे गोल में तब्दील नहीं सके। घाना ने भी जवाबी हमले किए और दूसरे हाफ में दोनों टीमों की तरफ से आक्रामक खेल देखने को मिला। क्रिस्टियन मार्टिनेज ने एक ढीली गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास साइड नेटिंग में चला गया और टीम बढ़त नहीं ले सकी।

ऑस्ट्रिया ने जीत के साथ किया आगाज, जॉर्डन को 3-1 से हराया

सांता क्लारा। फीफा वर्ल्ड कप में 28 साल में अपना पहला मैच खेलने उतरी ऑस्ट्रिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन को रोमांचक मुकाबले में 3-1 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करने वाली जॉर्डन की टीम ने ऑस्ट्रिया को कड़ी टक्कर देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन टीम को अपनी गलतियों के कारण खामियाजा भुगतना पड़ा। मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रिया को जॉर्डन की तरफ से कड़ी चुनौती मिली। मैच के दूसरे मिनट में जॉर्डन के कप्तान एहसान हद्दाद ने पहला मौका बनाया, लेकिन उनका शॉट साइड नेटिंग में चला गया। इसके बाद ओदेह फखौरी ने भी दूर से शानदार प्रयास किया, जिसे ऑस्ट्रिया के गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लेगर ने बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में जाने से रोक दिया। शुरुआती दबाव झेलने के बाद ऑस्ट्रिया ने 20वें मिनट में मैच का पहला गोल करते हुए बढ़त हासिल की। रोमानो श्मिड ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद जॉर्डन की टीम ने लगातार लड़ाई जारी रखी। दूसरे हाफ की शुरुआत के कुछ ही मिनट बाद अली ओलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रियाई डिफेंडरों को छकाते हुए बेहतरीन गोल किया। ओलवान वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जॉर्डन के पहले खिलाड़ी बने। इस गोल से स्कोर 1-1 हो गया। इसके बाद दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के प्रयास जारी रहे।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हैरी केन का कमाल

अर्लिंग्टन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हैरी केन ने इंग्लैंड की पहली जीत में अहम भूमिका निभाई। केन के दो दमदार गोल की बदौलत इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया। केन ने इन दो गोल के साथ ही खास उपलब्धि को भी अपने नाम कर लिया है। हैरी केन इंग्लैंड की ओर से फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान गैरी लिनेकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। केन विश्व कप में अब लिनेकर के बराबर 10 गोल कर चुके हैं। इस मुकाबले से पहले लिनेकर की बराबरी करने के लिए केन को 2 गोल की दरकार थी।

व्यापार

ब्रिटेन से 1.35 करोड़ डॉलर के ऑर्डर की खबर से रॉकेट बने किर्लोस्कर के शेयर

नईदिल्ली, एजेंसी। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। निवेशक इस स्टॉक को खरीदने के लिए उस वक्त टूट पड़े, जब कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे ब्रिटेन के एक कस्टमर से लगभग 1.35 करोड़ डॉलर का पिग आयरन इंपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस वजह से इस शेयर की कीमत 11.99 प्रतिशत की बढ़त के साथ 497.55 रुपये तक पहुंच गई और यह एनएसई पर टॉप गेनर बन गई। 11 बजे के आसपास स्टॉक करीब 10 प्रतिशत की उछाल के साथ 489 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 5 दिन में यह शेयर 18 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया है। जबकि, पिछले एक महीने में 15 प्रतिशत। एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए कंपनी ने बताया कि इस अनुबंध के तहत 30,000 मीट्रिक टन बेसिक ग्रेड पिग आयरन की सप्लाई फ्री ऑन बोर्ड के आधार पर की जाएगी। भुगतान की सुरक्षा के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रावधान किया गया है और इसकी अंतिम खेप 15 अगस्त, 2026 तक भेज दी जाएगी।

खरबपति बनने के बाद एलन मस्क को पहला झटका, 24 घंटे में ही 53,298 करोड़ स्वाहा

नईदिल्ली, एजेंसी। एलन मस्क की कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को शेयर करीब 5% टूट गए, जिससे लगातार तीन दिनों से जारी लगभग 50% की तेजी पर विराम लग गया। इससे एलन मस्क को एक ही दिन में 56.4 अरब डॉलर यानी 53,298 करोड़ का झटका लगा। मस्क के नेटवर्थ में आई यह गिरावट भारत के कई अरबपतियों के जीवनभर की कमाई के बराबर है। हालांकि, एलन मस्क के पास अभी भी 1.26 खरब डॉलर की संपत्ति है। इस साल मस्क का नेटवर्थ 640 अरब डॉलर उछला है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक नैस्डैक पर कारोबार के दौरान स्पेसएक्स के शेयर पहले 6% तक चढ़े थे, लेकिन बाद में बिकवाली हावी हो गई और स्टॉक लाल निशान में बंद हुआ। अमेजान से नीचे खिसकी स्पेसएक्स गिरावट के बावजूद करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर बना हुआ है। हालांकि कंपनी वैल्यूएशन के मामले में फिर से नीचे खिसक गई और दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इसके बावजूद शेयर अभी भी अपने 135 डॉलर के मूल्य से 42% से अधिक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से मुनाफावसूली और दबाव की वजह से आई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें तो स्थिर रखीं, लेकिन इस साल के अंत तक संभावित रेट हाइक के संकेत दिए। इसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ गई। 100 में 1% की कमजोरी के अलावा बॉन्ड यील्ड और डॉलर दोनों मजबूत हुए। इसका असर जैसे हाई-वैल्यूएशन टेक शेयरों पर भी पड़ा। कुल शेयरों में से केवल करीब 4.2% शेयर ही बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। कम फ्री-फ्लोट के कारण शेयर में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में जब लॉक-इन अवधि खत्म होगी और अंदरूनी निवेशक शेयर बेच सकेंगे, तब शेयर पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है।

रिटेल निवेशकों की पहली पसंद बना स्पेस एक्स - अमेरिकी रिटेल निवेशकों का सबसे पसंदीदा शेयर बन गया है। डेटा के मुताबिक, हर दिन में खुदरा निवेशकों की खरीदारी एनवीडिया, अल्फाबेट, मेटा और प्रमुख श्वञ्जस्र फंडों की संयुक्त खरीदारी के बराबर रही। दिलचस्प बात यह है कि इसी अवधि में मस्क की दूसरी कंपनी में लगभग 6.1 करोड़ डॉलर की शुद्ध बिकवाली हुई।

15 जुलाई से भारत में सस्ती हो जाएंगी स्कॉच व्हिस्की और गाड़ियां, भारत-ब्रिटेन के बीच हुई ऐतिहासिक डील

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और यूनाइटेड किंगडम (च) ने बुधवार को एक बड़ा एलान करते हुए घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता आगामी 15 जुलाई से पूरी तरह लागू होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक साल से भी कम समय के भीतर इसे लागू किया जा रहा है।

यूके के बिजनेस एंड ट्रेड विभाग के अनुसार, दोनों देशों के व्यवसायों और कंपनियों के पास अब इस नई व्यवस्था के तहत तैयारी करने के लिए 28 दिनों का समय है, जिसके बाद 15 जुलाई से वे नए नियमों के तहत व्यापार कर सकेंगे। इस डील से ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की और गाड़ियां समेत कई चीजें भारत में काफी सस्ती हो जाएंगी। इस ऐतिहासिक समझौते को अमलीजामा पहनाने में तीन साल से अधिक का समय लगा है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने पिछले साल 24 जुलाई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चेकर्स एस्टेट में इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुए थे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत-यूके द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन बताया था, जो दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि के रास्ते खोलेगा। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने इसे यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता करार दिया है। ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 2.7 लाख करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और दीर्घकालिक रूप से ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना लगभग 51,000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा। इस समझौते में कामकाजी पेशेवरों के लिए 'सोशल सिक्योरिटी' से जुड़ा एक बड़ा प्रावधान शामिल किया गया है। काम के सिलसिले में यूके से भारत आने वाले या भारत से यूके जाने वाले पेशेवरों के लिए बिना वहां सोशल सिक्योरिटी टैक्स चुकाए नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जारी रखने की अवधि को 36 महीने से बढ़ाकर सीधे 60 महीने (5 वर्ष) कर दिया गया है।

भारत आने वाले ब्रिटिश सामान पर असर

भारत ने यूके से आने वाले 90% उत्पादों पर सीमा शुल्क यानी टैरिफ कम करने या पूरी तरह हटाने पर सहमति जताई है। स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाली 150% ड्यूटी पहले ही दिन घटकर 75% हो जाएगी और अगले 10 वर्षों में यह घटकर केवल 40% रह जाएगी। ऑटोमोटिव (गाड़ियां और ऑटो पार्ट्स) टैरिफ को एक निश्चित कोटे के तहत 100% से घटाकर सीधे 10% कर दिया जाएगा। मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स, एयरोस्पेस पार्ट्स और वाइन-फूड प्रोडक्ट्स पर भी भारी कटौती होगी। कॉस्मेटिक्स पर लगने वाली 22% तक की ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यूके भारत से आने वाले 99% सामानों पर टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर देगा। लागू होते ही पहले साल में यूके से भारत होने वाले निर्यात पर लगभग 3,400 करोड़ रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो 10 साल बाद बढ़कर 7,650 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकती है।

1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने की तैयारी में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

नईदिल्ली, एजेंसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर गुरुवार को बाजार खुलते ही झूम उठे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने 30000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आईपीओ के लिए बाजार नियामक संस्था सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। इसी के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 188.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 214.75 रुपये है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ड्रॉफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों में से है। न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑफर फॉर सेल के जरिए 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 1.05 करोड़ रुपये बेचेगी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रत्येक शेयर की वैटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0.32 रुपये है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बुधवार को अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास प्रीलिमनरी पेपर्स जमा कर दिए हैं। एनएसई के आईपीओ का साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये का है। इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में यह शेयर सेल सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू होगा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक इश्यू पूरी तरह से 14.89 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल होगा। मौजूदा शेयरधारक एक्सचेंज में संयुक्त रूप से करीब 6 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचेंगे। हस्श्व के इस प्रस्तावित आईपीओ से सरकारी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और लंबी अवधि से निवेश बनाए रखने वाले कई इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को फायदा होगा। मौजूदा निवेशकों ने कई सालों पहले बहुत कम दाम पर एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी थी।

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1.066 करोड़ तक शेयर बेचेगा। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 5.26 रुपये प्रति शेयर के दाम पर एक्सचेंज के शेयर खरीदे थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने भी 1 रुपये प्रति शेयर से कम पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी थी। यह कंपनी आईपीओ के जरिए एक्सचेंज में अपनी थोड़ी-थोड़ी हिस्सेदारी बेच रही हैं। हस्श्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3.23 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)